हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 1992

खण्ड–1, अंक–6

अधिकृत विवरण

विशत सूची

सोमवार, 16 मार्च 1992

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(6)23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)25
वर्श 1992–93 का बजट पेश करना	(6)30
वाक–आउट	(6)55

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 मार्च, 1992

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौ. ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Upgradation of High Schools

***153. Sh. Jai Pal Singh**: Will the Miniser for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Government High School, Janti Kalan and Nangalan Kalan respectively; if so, the time by which these schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): जी नहीं।

श्री जयपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा इलाका एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगता है और दूसरी तरफ दिल्ली से लगता हैं इस क्षेत्र में लगभग 20 गांवों में कोई भी मिडल या हाई स्कूल नहीं है। 20 मील के एरिया में कोई भी 10 जमा 2 का स्कूल नहीं है। मैं आदरणीय बहन जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कब तक स्कूल अपग्रेड करेंगे?

श्रीमती शान्ति देवी राठी: मेरे माननीय सदस्य सोनीपत के राई हल्के के हैं और इन्होंने कहा है कि वहां पर कोई भी 10 जमा 2 का स्कूल नहीं हैं। स्पीकर साहब, पिछले वर्श ही मैंने नाहरा में 10 जमा 2 स्कूल अपग्रेड किया है जो कि इनके क्षेत्र में ही पड़ता है। जठेड़ी में भी हाई स्कूल है और ये कह रहे हैं कि वहां पर कोई हाई स्कूल नहीं है। स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनको थोड़ी सी और जानकारी भी दे दूं कि दो और स्कूल भी है। एक तो जाटीकलां में है जो कि दिल्ली के बार्डर पर पड़ता है और दूसरे बीच में रोड़ के पास ही सिद्धू सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पड़ता है। गांवों के बच्चे वहां पर जाते हैं, यह स्कूल दिल्ली में पड़ता है और 10वीं के बाद बच्चे बराबर वहां से लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली भी अपने ही एरिया जैया है। नांगल कलां तथा 3–4 और गांव वहां साथ लगते हैं जो कि उस स्कूल से लाभ उठा सकते हैं। आने वाले वित्त वर्श में इनके हल्के में स्कूल अपग्रेड करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सं माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से यह जानकारी चाहूंगा कि स्कूल के दर्जा बढ़ाने का कोई खास क्राईटेरिया है अथवा जिस स्कूल का चाहा दर्जा बढ़ा दिया और जिसका चाहा रहने दिया। क्या मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगी कि स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए पोलिटिकल क्राईटेरिया है या कोई और क्राईटेरिया है?

श्रीमती शान्ति देवी राठी: स्पीकर सर, ऐसा कोई क्राईटेरिया नहीं है लेकिन कम से कम शिक्षा का विस्तार हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन लोगों की सरकार ने जाते–जाते 350 स्कूलों को अपग्रेड किया था। इन स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए न तो योजना विभाग से अनुमति प्राप्त की गई और न ही वित्त विभाग से बजट का प्रावधान करवाया था। यही वजह है कि वे स्कूल अपग्रेड नहीं हो सके। उसके बाद जितने भी स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, वे बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी राजनैतिक निर्णय के आधार पर किये गए हैं।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो स्कूल 27.3.1991 को अपग्रेड किए गए थे उसका निर्णय एक बैठक में हुआ था और उस बैठक में मिनिस्टर चेयरमैन थे। ऐजुकेशन सैक्रेटरी भी थे, डायरैक्टर भी थे और उस कमेटी का मैम्बर होने के नाते मैं भी उस बैठक में था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आपके अपने हल्के का भी कोई स्कूल अपग्रेड हुआ या नहीं?

श्री सतबीर सिंह कादयान: एक भी स्कूल वहां पर अपग्रेड नहीं किया गया। इदाना में स्कूल अपग्रेड किया जाना था लेकिन वह उरलाना में कर दिया जब कि इदाना गांव उससे काफी बड़ा है लेकिन उरलाना शिक्षा मंत्री महोदया के गोत का गांव है,

इसलिए इदारा को अपग्रेड नहीं किया गया। मैं शिक्षा मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उसको ये कब अपग्रेड करेंगी?

श्रीमती शान्ति देवी राठी: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का आरोप बिल्कुल निराधार है। इनके अपने क्षेत्र इदारा गांव में आलरेडी स्कूल है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वहां पर मिडल स्कूल अपग्रेड किया गया था, क्या वह भी मेरे गोत का है? वहां के वोट तो आपने ही लेने हैं लेकिन ऐसी भाशा का प्रयोग कम से कम आपको इस सदन मे ंतो नहीं करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से खुश हूं कि बहन शांति राठी जी ने नगलांकला के बारे में कुछ आश्वासन दिया और देना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, 8 दिसम्बर के जलसे में मुख्यमंत्री जी ने 10+2 स्कूल नाहरी में बनाने का एलान किया था। (विघ्न) वह तो आपकी इस साल की लिस्ट में आ गया होगा। उसको बनाने का कुछ प्रावधान कीजिए।

श्रीमती शान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, इस वित्त वर्श में मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था, वह मामला विचाराधीन है।

श्री के.एल. शर्मा: स्पीकर साहब, जो स्कूल ओरिजनल लिस्ट में अपग्रेड किए गए थे, उनके अलावा कुछ ऐसे स्कूल रह गए थे, जो सारे क्राईटेरिया पूरे करते थे। इन स्कूलों की सारी

बातों को देखकर और जनता की पुरजोर मांग पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपग्रेडेशन मुख्यमंत्री जी ने यह शिक्षा मंत्री महोदया ने बाद में अनाउंस की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनकी क्लासिज पहली लिस्ट वाले स्कूलों के साथ ही शुरू की जाएंगी यहा बाद में शुरू की जाएंगी?

श्रीमती शान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कोई विशेश स्कूल माननयी सदस्य के ध्यान में हो तो बता दें, हम विचार कर लेंगे लेकिन यह कहना कि इतना अनाउंस किया था, यह इस वक्त सम्भव नहीं है।

श्री के.एल. शर्मा: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्युएंसी में एक झांसा गांव है जो सारे क्राईटेरियाज पूरे करता है और मुख्यमंत्री जी ने मेरी कांस्टीच्युऐंसी शाहबााद में अपनी विजिट के दौरान 19 जनवरी 1992 तक उसकी अपग्रेडेशन अनाउंस की थी। तो मैं उसके विशय में जानना चाहूंगा कि क्या वे क्लासिज इसी साल शुरू की जा रही है? (विघ्न)

श्रीमती शान्ति देवी राठी: स्पीकर साहब, हमारी विपक्ष के भाइयों की तरह की कोई परम्परा नहीं है। यह कांग्रेस कलचर है और जैसा हम आश्वासन देंगे या वचन देंगे, वहां हम स्कूल या कालेज को अवश्य बनाएंगे।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, 1986 में कवारी गांव में और जमालपुर गांव में 10+2 स्कूल की नई बिल्डिंग 10 लाख 41

हजार रूपए खर्च करके बनाई गई थी परन्तु वह पूरी नहीं हुई थी। तो क्या उसको इस साल में बनाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती शान्ति देवी राठी: अध्यक्ष महोदय, अभी इनकी और से और पंचायत की ओर से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है और यह क्वैश्चन अभी असैम्बली में ही इन्होंने उठाया है। इसको यदि आप हमें लिखकर भेज दें तो हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

32 K.V. Sub-Station at Village Alewa

***129. Sh. Ram Kumar Katwal**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 32 K.V. sub-station at village Alewa; if so, the time by which it is likely to be set up; and

(b) if the reply to in part (a) above is in affirmative, the number of village to which electricity is likely to be supplied through the above-said sub-station?

Irrigation and Power Minister (Sh. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes, Sir. The 33 KV sub-station at village Alewa is likely to be commissioned by March, 1993.

(b) Ten villages will be benefitted by the above sub station.

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, इसमें मैंने यह भी पूछा था कि उस सब–स्टेशन से क्या कोई चक्की या छोटी–मोटी फैक्टरी भी चल सकती है या नहीं चल सकती है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सब–स्टेशन से कोई रेलगाड़ी या बैलगाड़ी तो नहीं चलाई जा सकती है। उससे तो चक्की और टयूबवैल ही चलाए जाएंगे। इसके बारे में इनको यह ब्योरा देना चाहूंगा कि इस वक्त अलेवा और उसके आस पास के जो गांव है, उनको रगुरा और राजौंदा सब–स्टेशन से 33 के.वी. बिजली मिलती है। यह लाईन ओवर लोडिड है। इनके गांव अलेवा और अरेना टेल एंड पर हैं इसलिए वहां वोलटेज का प्रोब्लम है। 17.12.91 को उसका फाऊंडेशन स्टोन रखा गया था और मार्च 1993 तब बन कर पूरा हो जाएगा। इस पर करीब 60–70 लाख रूपए खर्च होंगे। इसमें 10 गांव हैं जिनके नाम हैं– सांडा, अलेवा, कटवाल, गुड़ाना, भिगाना, गंगाठेड़ी, कोपड़ा, कोल, जोली और ऐलोल जिनको इस सब–स्टेशन से फायदा पहुंचेगा। इन गांवों में जो 5 हजार के करीब कंज्यूमर्ज हैं, उनको भी फायदा होगा और 250 टयूबवैल के जो पैंडिंग कनैक्शनज पड़े हैं, वे भी रिलीज हो जाएंगे। इससे इनको ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलेगी और वोलटेज भी ठीक होगी, उसमे ंचाहे ये चक्की चलाएं या मोटर चलाएं।

श्री कृश्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि असन्ध के अन्दर 132 के.वी.

सब–स्टेशन अन्डर कन्स्ट्रक्शन है, वहां पर 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर रखा गया था लेकिन वह वहां से रात को चोरों की तरह उठा लिया गया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्रांसफार्म वहां से क्यों उठा लिया गया?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न अपने मेन–सवाल में नहीं पूछा है और न ही मुझे यह पता है कि यह ट्रांसफार्मर चोरी भी हुआ है या नहीं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हू कि असंध का सब–स्टेशन हम जल्दी ही पूरा करने जा रहे हैं। इसका सिविल वर्क्स पूरा हो चुका है, इंस्टालेशन पूरी हो चुकी है तथा लाइन भी बन चुकी है और इसके लिए ट्रांसफार्मर झांसी से असन्ध के लिए लोड हो चुका है और वह अगली पैडी सीजन से पहले ही चालू हो जायेगा।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अलेवा सब स्टेशन के अलावा जो नकीपुर का सब–स्टेशन है और जिसकी नींव भी रखी हुई है, क्या सरकार नकीपुर सब–स्टेशन को बनाने का इरादा रखती है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नकीपुर सब–स्टेशन के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछा ओर न ही मुझको यह पता है कि नकीपुर सब–स्टेशन कहां पर है? लेकिन मैं इनको एक बात बता सकता हूं कि हमने इस साल 220 के.वी. का सब–स्टेशन भिवानी में चालू किया है। इसके अलावा, 132 के.

वी. के चार सब–स्टेशन सीवड़, धारसू, राढ़िया तथा मधुपुर में हैं तााि 66 के.वी. के 5 बस स्टेशंज उरलाना, बग्गा, सिसवाड़, पानीपत और किलाना में हैं जो एनर्जाइज हो चुके हैं और औगमैंट हो चुके हैं जिनकी कैपेसिटी इस प्रकार है: 2 सब–स्टेशनों की 220 के.वी. आठ सब–स्टेशन ों की 132 के.वी. औगमैंट है। इसके अलवा 8 सब स्टेशनों की 66 के.वी. की और 18 सब स्टेशनों की 33 के.वी. की औगमैंट है। जिन पर काम चल रहा है वह हैं शाहबाद की 220 के.वी., असन्ध मे 132 के.वी. चंदौली, अमीन और बीड़ में 66 के.वी.। इसके अलावा अम्बाला सिटी, बग्गैड़, शहाजादपुर, चिंदौर, डूंडाहेड़ा और बिलासपुर में सात सब–स्टेशन 33 के.वी. के प्रोग्रैस कर रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने फरमाया है कि 220 के.वी. के सब–स्टेशनों पर कई जगह काम चल रहा है। क्या नम्बर आफ टयूबवैल्ज, अगर सबसे अधिक किसी डिवीजन में हैं, तो क्या टेल की बात को ध्यान में रखते हुए, महेन्द्रगढ़ में 220 के.वी. का सब–स्टेशन बनाने का इराजा है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस समय महेन्द्रगढ़ जिले की स्पैशल सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बता सकता हूं कि रिवाड़ी नारनौल, महेन्द्रगढ़ के सारे इलाकों में, इस सरकार ने आने के बाद हर सब–स्टेशन को औगमैंट किया है। कहीं पर 25 एम.वी.ए. के और कहीं पर 50 एम.वी.ए. के नये ट्रांसफारमर्ज रखे गये हैं,

जबकि इससे पहले, जब इनकी सरकार आयी थी तो इन्होंने इन इलाकों को बहुत ज्यादा निगलैक्ट कर दिया था। इन इलाकों में टयूबवैल्ज गहरे हैं और पानी की मिकदारकम है, साथ ही बिजली की कमी की वजह से बड़ी दिक्कत होती थी लेकिन अब वहां पर काफी इम्प्रूवमैन्ट हो चुकी है। इसके अलावा, महेन्द्रगढ़ के सब–स्टेशन को हम 220 के.वी. का सब–स्टेशन बनाने जा रहे हैं लेकिन यह सब–स्टेशन अगले फाइर्नेशियल ईयर तक ही पूरा हो पायेगा।

चौ. फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना और जानना चाहूंगा कि वे बराड़ा और सढ़ौरा के 132 के.वी. सब–स्टेशन का काम कब तक पूरा कर देंगे क्योंकि वहां पर पावर फलक्चुएशन की वजह से दिक्कत है? वहां पर वोल्टेज स्टेबेलाईजेशन की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुलाना का तो 33 के.वी. का आगमैंटेशन होना ही चाहिये। इसके अलावा, खेड़ा में एक पावर स्टेशन का कन्ट्रोल बी.बी.एम.बी. के पास है और वे उसकी सप्लाई काट देते हैं। इसका प्रबन्ध भी कब तक कर दिया जायेगा?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि फूल चन्द मुलाना जी एक बहुत ही जागरूक सदस्य हैं। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वे अपने इलाके के कामों के बारे में मुझे ही नहीं, सरकार में सब को निरन्तर मिलते रहते हैं और पता करते रहते हैं। जहां तक

उनकी इस स्कीम की बात का ताल्लुक है और जो इन्फर्मेशन इन्होंने पूछी है, उसकी डिटेल्ड इन्फर्मेशन इस समय मेरे पास नहीं है। बहरहाल असैम्बली से बाहर में उनको यह इन्फर्मेशन दे दूंगा। श्री राम बिलास शर्मा जी के सवाल का जहां तक ताल्लुक है कि कनीना, नारनौल और महेन्द्रगढ़–तीनों गजह के सब–स्टेशन की आगमैंटेशन का काम किस स्टेज पर है, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि इन पर काम पहली या दूसरी स्टेज पर चल रहा है। जल्दी ही यह औगमैंट हो जायेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि महेन्द्रगढ़ में 220 के.वी. सब–स्टेशन का काम अन्डर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यह काम अगले से अगले साल में जाकर पूरा हो सकेगा।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आदरणीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि असंध के ट्रांसफार्मर की चोरी के बारे में उनको पता नहीं है लेकिन इतना तो उन्हें पता होगा कि वहां पर सारा काम बनकर तैयार हो गया था, ट्रांसफार्मर भी आ गया था लेकिन यही ट्रांसफार्मर कहीं और लगा दिया गया? केवल एक ट्रांसफार्मर न मिलने की वजह से सारा काम रूका पड़ा है। क्या यह बात आपके नोटिस में है कि चोरी नहीं हुई है, बल्कि उसकी कहीं दूसरी जगह पर बदला गया है? क्या आप इस बारे में पता करके बतायंगे? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि आगुमैटेशन आफ सब–स्टेशन्ज और नये सब–स्टेशन्ज जो बन रहे हैं, दोनों किस्म के काम की स्कीमें आपकी सरकार के आने से पहली कितनी थीं, और आपने आने के बाद कितनी बनायी है? मेरा पूछने का मकसद

यह है कि जो सब–स्टेशन बनाये जा रहे हैं या अन्डर प्रोसैस है, जिनकी आगमैंटेशन होनी थी, आज की सरकार आने से पहले कितने थे और इस सरकार ने आने के बाद नये कितनों पर काम शुरू किया है?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जिस ट्रांसफार्मर की बात इन्होंने फिर से चलायी कि उस सब–स्टेशन के काम को ऐक्सैलरेट करके पूरा करवाया था, जब इंस्टालेशन का सारा काम अन्डर कंस्ट्रक्शन था ओर पूरा होने के लगभग नजदीक था तो वहां से ट्रांसफार्मर उठा लिया गया। इस बारे में मेरा कहना यह है कि जो असन्ध के बारे में इन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, इनको ज्यादा पता होगा। अगर इन्होंने वहां से उतरवाया होगा तो यह ही बता सकेंगे कि क्या बात है। बाकी सैकेंड सवाल का जहां तक सम्बन्ध है, उस बारे में मेरा कहना यह है कि इनको बाकी के कामों के फुरूसत मिले, तब तो यह सवाल पूछें। मैं आफ हैंड इनको कैसे यह सब कुछ बता सकता हूं कि इनके वक्त में क्या काम शुरू हुआ था और क्या नहीं। माननीय सदस्य ने इस बारे में कोई क्वैश्चन पूछा ही नहीं है। (व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, माननीय मंत्री महोदय ने सारी स्टेट के आंकड़े खुद अभी दिये हैं। सवाल केवल अलेवा के सब–स्टेशन्ज का था लेकिन ये इतने इन्टैलीजैंट हैं कि सारी स्टेट का ब्यौरा दे दिया है। जब ये इतने इंटैलीजैंट है तो जो

आउटगोईंग सरकार की इस बारे में स्कीम्ज थीं, वे भी बता सकते हैं कि कितनी थीं और इन्होंने खुद कितनी शुरू की है। मेरा तो इस बारे में बिल्कुल स्पश्ट सवाल था। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा, स्पीकर साहब, कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इनको जवाब देने के लिये कहें अगर अभी ये जवाब नहीं दे सकते तो इस सवाल को पोस्टपोन कर दें। कल को जवाब दे दें, परसों को दे दें। दो चार–छः दिन के बाद कभी भी टाईम निश्चित कर दैं, तब जवाब दे दें। (व्यवधान व शोर) ....

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मेरे माननीय सदस्य ने बड़ी डिटेल में इंफर्मेशन मांगी है जोकि पहले नहीं पूछी गई थी। इसके लिये ये अलग से नोटिस दे दैं तो हम सारी सूचना इनको दे दैंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, आप अपने निजी प्रभाव से इनको कहें कि ये हमारे प्रश्न का सही जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। इस तरह से सवाल पहले भी आते रहे हैं और उनके उत्तर भी आते रहे हैं। आप इसके लिये अलग से नोटिस दे दीजियेगा।

श्री कृश्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं। हमारे हल्के के ट्रांसफारमर को सरकार ने शिफट करके मधुबन भेज दिया है। क्या सरकार वहां से

ट्रांसफारमर शिफट करने का कारण बताएगी कि ऐसा क्यों किया गया ह?

(इस प्रशन का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Reduction in strength of I.A.S. Officers

***183. Sh. Karan Singh Dalal**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the strength of I.A.S. & H.C.S. Cadre posts of the State as an austerity measure; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken int eh matter?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत से सरकारी विभाग ऐसे हैं जो टैक्नीकल हैं जैसे कि इरीगेशन एण्ड पावर व लोक निर्माण विभाग हैं, जिनके हैडज आफ दा डिपार्टमैंटस इंजीनियर्ज होने चाहिये लेकिन सरकार ने उनके कमिश्नर व सेक्रेटरी आई.ए.एस. अधिकारी ही लगा ररहे हैं। मेरा कहना यह है कि इन विभागों के जो हैडज हैं, वे टैक्नीकल आदमी ही होने चाहियें। इंजीनियर्ज ही होने चाहियें ताकि टैक्नीकल विभागों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरा मेरा

प्रश्न यह है कि शूगर मिलों में भी सरकार ने एच.सी.एस. आफिसर्ज लगा रखे हैं लेकिन उनकी जगह कोई टैक्नीकल इंजीनियर्ज ज्यादा अच्छा काम चला सकते हैं। क्या सरका एच.सी. एस.त्र अधिकारियों के स्थान पर इंजीनियर्ज को ही लगाने की प्राथमिकता देंगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननयी सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि कहीं काम ऐसे होते हैं जहां टैक्नीकल आदमी ही लगाये जाते हैं, जैसा कि इन्होंने इरीगेशन एण्ड पावर विभाग वगैरह का जिक्र किया लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि टैक्नीकल विभागों के इंजीनियर–इन–चीफ जो हैं, वे इंजीनियर्ज ही होते हैं, लेकिन इन विभागों के ऊपर कमिश्नर से सैक्रेटरी आई.ए.एस. आफिसर्ज ही होंगे। जहां तक शूगर मिलों में सच.सी.एस. अफसर लगाने का सवाल है, उस बारे में ऐसा है कि जहां इंजीनियर्ज को काम करने की जरूरत होती है, वहां इंजीनियर ही काम करता है लेकिन जहां ओवर आल ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का सवाल होता है, वहां पर एच.सी.एस. अधिकारी ही लगाये जाते हैं ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन का का सुचारू रूप से चलता रहे।

प्रो. छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने दो दिन पहले इस हाउस में यह कहा था कि हम हरियाणा के अन्दर 30 स्पैशल एच.सी.एस. अधिकारियों की भर्ती कर रहे हैं और अब हाउस में कह रहे हैं कि हम एच.सी.एस.

अधिकारियों की संख्या घटा रहे हैं। इस तरह उनके कहने से इस सदन में थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में स्पश्टीकरण देंगे कि सही स्थिति क्या है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे हरियाणा केडार के 216 एच.सी.एस. अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। उनमें केवल इस समय 120 हरियाणा के अन्दर तैनात हैं। 23 आदमियों, जिनकी पहली सकरार ने इन्टरव्यू ले रखी है, के नाम आने वाले हैं और 30 आदमी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम बाकायदा डायरैक्ट भर्ती कर रहे हैं। जो वेकेन्सीज बाकी बची हैं, उनके बारे में हमारी कोशिश होगी कि वह जल्दी ही भर ली जाएं और यह देखना है कि बाई परमोशन कितनी और डायरैक्ट कितनी भर्ती बनती है।

Repair of damaged roads in Beri Constituency

***121. Ch. Om Parkash Beri**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged roads inthe Beri Constituency of Rohtak District; and

(b) if so, the time by which the roads as referred above are likely to be repaired?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) बेरी हल्के में सारे कार्यों की मुरम्मत जिन की पहचान की गई है, 31.3.92 तक पूरा करने की संभावना है।

चौ. औम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि बेरी कांस्टीच्यूएंसी में रोडस की जो रिपेयर होनी थी, उसके बारे में पता लगा लिया है। यह बात सही है लेकिन अभी अभी मैं अपने हल्के में गया था, ठीक है कुछ सड़कों पर रिपेयर का काम शुरू है परन्तु कुछ सड़कों पर अभी रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि सरकार की नई नीति के अनुसार जिन गांवों के अन्दर से सड़कें गुजरती हैं, उन सड़कों की रिपेयर तभी होगी जब उनके दोनों तरफ ड्रेन्ज बना दी जाएंगी। इन ड्रेन्ज को गांवों में तो विकास विभाग बनाता है और शहरों में म्यूनिसिपल कमेटीज बनाती है। क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि चूंकि इनका प्रोपर कोआर्डिनेशन नहीं हैं, इसलिए क्या वे विभाग के अफसरों को हुक्म देंगे कि वे प्रोपर कोआर्डिनेशन रखें ताकि सड़कों के रिपेयर के काम में रूकावट न हो? साथ–साथ में यह भी आश्वासन चाहूंगा कि अब तक कुछ सड़कों पर काम ही शुरू नहीं हुआ है और ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती कि उनको काम 31 मार्च तक कम्पलीट हो जाएगा। क्या वे आश्वासन देंगे कि उस कांस्टीच्यूएंसी में सभी सड़कों की रिपेयर का काम डेढ़ दो महीने में मुकम्मल हो जाएगा?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब के हल्के में 21 सड़कों की हालत ठीक नहीं थी। उनमें से 11 सड़कों पर काम

कम्पलीट हो चुका है और 10 सड़कों पर काम चल रहा है। बेरी हल्के के लिए 48.64 लाख रूपया दिया जा चुका है जिसमें से 35. 80 लाख रूपए खर्च हो चुके हैं। जहां तक महकमा ड्रेनेज का सड़कों के साथ ताल्लुक है, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो नीचे रह जाती हैं तो उसके लिए ड्रेन का काम भी जरूरी है इसलिए महकमा इरीगेशन इनसे कोआर्डिनेशन करता है। हम कोशिश करेंगे कि 31 मार्च तक सारी सड़कें कम्पलीट हो जाएं।

Domestic water connections

***136. Sh. Amar Singh**: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give domesitc water connections at Siwani in District Bhiwani; and

(b) if so, the time by which the aforesaid connections are likely to be given?

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gaub):

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, सिवानी सब–डिवीजन जैसा जुडिशियल कम्पलैक्स सारे हरियाणा में सब डिवीजनल लैवल

पर कहीं भी नहीं है। क्या वहां पर घर घर में नलके देने का प्रावधान करेंगे?

चौ. धर्म वीर गाबा: स्पीकर साहब, पर–डे, पर–कैपिटा पानी देने का क्राइटेरिया पापुलेशन पर निर्भर है। जहां आबादी 20 हजार की है, वहां पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 20 गैलन पानी देते हैं। जहां बी–क्लास म्यूनिसिपल कमेटी है, वहां पर 25 गैलन पानी देने हैं और ए–क्लास कमेटी जहां पर है, वहां पर 40 गैलन देते हैं। इसमें पापुलेशन की बात है। सिवानी की पापुलेशन 13 हजार की है, वहां पर 10 गैलन पानी देते हैं। इसमें सब–डिवीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। आगे के लिए हम एक स्कीम बनाने जा रहे हैं उसके बाद पानी ज्यादा मिलेगा।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि सिवानी में म्यूनिसिपल कमेटी है, वह सब–डिवीजन है और वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठता है, यानी वहा सारा क्राइटेरिया पूरा करता है। वहां पर स्टैंड पोस्ट भी बहुत कम हैं। आज कल वहां पर पानी के लिए लोगों के जूते बजते रहते हैं। खेद की बात यह है कि सब–डिवीजन लैवल पर, (सिवानी में) घर घर में पानी देने की व्यवस्था नहीं है। बाकी सभी जगहों पर है तो क्या इस मांग को जल्द मीट–आउट करेंगे?

चौधरी धर्मबीर गावाः स्पीकर साहब, मै पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सैनिटरी बोर्ड से 1981 से इन काम के लिए 25 लाख मिले थे और यह काम चालू हो गया था। फिर 1985 में यह पैसा बढ़ा कर 41 लाख रूपय कर दिया गया था। अब हम आबादी के हिसाब से पीने का पानी 10 गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति बढ़ा देंगे और घर घर में पानी का कनैक ान देने का प्रावधान करेंगें

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य थी अमर सिंह जी के सवाल के जवाब में बताया है कि पीने का पानी आबादी के हिसाब से देने का काइटेरिया है। सिवानी कस्बे की आबादी चूकि 20 हजार से कम है लेकिन इस बैकवर्ड इलाके में आबादी चाहे कम ही इस सब–डिवीजन बनाने की आव यकता थी, इसलिए सरकार ने सिवानी को सब डिवीजन बना दिया। अब सवाल उठता है कि जो कस्बा सब–डिवीजन बन जाता है, उसका स्टेटस बढ़ जाता है, चाहे वह पहले गांव ही क्यों न रहा हो। सरकार नई स्कीम के तहत 10 गैलन पानी की मात्रा बढ़ा कर 20 गैलन करने जा रही है। स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ाए बगैर सरकार घर घर में पीने के पानी का कनैक्शन नहीं दे सकती। स्पीकर साहब गवर्नमैंट औफ इंडिया की भी वाटर वर्कस को औगमैंट करके, हर गांव में घर घर में पीने के पानी के कनैक्शन देने की स्कीम है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिवानी को सब–डिवीजन न मान करके, करके गांव कर उसमें

उस स्कीम को लागू करेंगे जिसमें 70–80 गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन देने का प्रावधान है? क्या उस स्कीम को लागू करके सिवानी सब–डिवीजन के हर घर में पीने के पानी का कनैक्शन देंगे?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसी 31 मार्च तक हरियाणा प्रान्त के हर गांव में पीने का स्वस्छ पानी पहुंचाने का प्रोग्राम है। इस 31 मार्च के बाद अगले साल के लिये हमारा यह फैसला करने का विचार है कि प्रान्त के जो बड़े–बड़े गांव हैं, जिनकी आबादी 10 हजार या 10 हजार से ज्यादा है, पहले उन गांवों के घर–घर में पीने के पानी के कनैक्शन देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे फैजवाइज टेकअप करेंगे। फर्स्ट फेज में कौन से गांव होने चाहिएं, सैकिण्ड फेज में कौन से गांव होने चाहिएं और थर्ड फेज में कौन से गांव होने चाहिए, यह फण्डज की अवेलेबिलिटी और पानी की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। जहां तक सिवानी सब–डिवीजन का ताल्लुक है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिवानी एक बहुत बड़ा कस्बा है। जब हम फेजवाइज पानी के कनैक्शन देने का मामला टेकअप करेंगे, उस समय उसको फर्स्ट फेज में टेकअप करेंगे।

श्री राम भजन अग्रवाल: स्पीकर साहब, भिवानी नगर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शहर है और वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है। मुझे कल पता लगा है कि भिवानी में पीने का पानी दो टाईम की बजाये एक ही टाईम दिया जा रहा है और उसका भी

पता नहीं है कि वह किस टाईम दिया जा रहा है। मुझे यह भी पता लगा है कि उस वाटर वर्कस की डिग्ग्री में केवल दो दिन का ही पानी है। अगर दो दिन के बाद भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी नहीं आया तो शायद भिवानी शहर के लोग पीने के पानी से महरूम रह जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहात हूं कि क्या उनके नोटिस में यह बात है, यदि है तो सरकार उसका क्या समाधान करेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल से इस सप्लीमैंटरी का ताल्लुक तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हो सकता है उस वाटर वर्कस की दो डिग्गियों में से एक डिग्गी की सफाई करने के लिये उसकी खाली कर रखा हो, और यह भी हो सकता है कि दूसरी डिग्गी में पानी कम हो इसलिये वाटर सप्लाई का टाईम कम कर दिया गया हो। हम भिवानी शहर के लोगों को पीने के पानी की कम नहीं रहने देंगे।

Providing outlets from Gurgaon Canal

***147. Prof. Chhatter Singh Chauhan**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide outlets from Gurgaon Canal to irrigation the land of Chhainsa village of Tehsil Hathin District Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid outlets are likely to be provided?

Irrigation and Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala):

(a) No, Sir.

(b) Question does nor arise.

प्रो. छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, जो गुड़गांव कैनाल है उसके साथ साथ चार गांव स्वामिका, उड़ीथल, छांयसा और विद्यावली है, जिनकी जमीन की छाती चीरते हुए यह गुड़गांव कैनाल निकालती है लेकिन आज तक उन गांवों की जमीन को उस कैनाल का पानी नहीं लग रहा है। आपके माध्यम से मैं आई. पी.एम. साहब से जानना चाहता हूं कि उन गांवों की जमीन को गुड़गांव कैनाल का पानी क्यों नहीं लग रहा है और कब तक लगना शुरू हो जाएगा?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जो गुड़गांव कैनाल है वह आगरा कैनाल से निकलती है और यह औखला से साढ़े चार किलोमीटर डाउन स्टीप निकलती है। उसकी 2200 क्यूसिक्स पानी की कैपेसिटी है लेकिन उसमें केवल 280 क्यूसिक्स पानी चलता है, बाकी का पानी एस.वाई.एल. नहर कम्पलीट होने के बाद ही चलेगा। बरसात के मौसम में जब जमुना के अन्दर ज्यादा पानी होता है तो उस समय इसमें फालतू पानी चलता है। यह कैनाल 1965 में बनी थी। इसमें जो मंडकोला

डिस्ट्रिब्यूटरी है, जिसमें झांसा गांव भी लगता है, यह उस गांव से निकलती है और इसकी कैपेसिटी 22 क्यूसिक है। यह जो नहर है, इसमें कोई डायरेक्ट आउटलेट मेन नहर में से या ब्रांच में से देने की सरकार की कोई नीति नहीं है। चूंकि गुड़गांव कैनाल भी ऐसी नहर है, इसलिये उसमें से सीधा आउटलेट नहीं दिया जा सकता।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह गुड़गांव कैनाल मेरे क्षेत्र से गुजरती है और इसकी कम से कम 8–10 किलोमीटर की जो लैंगि है, उसमें काफी मात्रा में घास और पटेरा खड़ा हुआ है जिसकी आज तक सफाई नहीं हुई है। इसकी वजह से आधे से ज्यादा पानी वेस्ट होता है और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी है, जिनका वेस्ट वाटर भी इस कैनाल में इलीगल ढंग से या अनअथोराइज्ड ढंग से पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि यह पानी आगे चल कर जब इन गांवों की तरफ जाता है तो उसको गांवों के लोग मवेशियों के लिये इस्तेमाल करते हैं जो मवेशियों के लिये बहुत ही खतरनाक होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन दोनों प्रौब्लम्ज से छुटकारा दिलाने के लिये कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने का आश्वासन सदन में देंगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय जो पटेरा और घास वर्गैरा की बात है, उसका कारण तो साफ है कि 2200 क्यूसिक्स की नहर है और उसमें 280 क्यूसिक्स पानी चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि पटेरा और घास के पैदा होने के लिये

280 क्यूसिक पानी भी काफी है। अगर पूरी नहर में पानी चलेगा तो उसकी रैगूलर सफाई होगी। यानि इसकी मेन्टीनेंस पर इतनी ज्यादा कास्ट आयेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने पिछले 4–6 महीने में इस तरफ ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री जी भी उस इलाके में गए थे और उन्होंने मेवात में ऐलान किया था खास कर इस नहर की सफाइ के बारे में। हम इस नहर की सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन इसकी लाईनिंग में कुछ डिफैक्ट है और सारे सिस्टम काो ठीक करने की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। जो छोटी–छोटी नहरें निकली है, उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इमसें पानी लिफ्ट करने के पम्प 25 साल पहले के थे। उनको भी अब रिप्लेस कर रहे हैं। इस तरह से इस कैनाल की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं और फैक्टरियों का जो गन्दा पानी इसमें गिरता है, उसको रोकने के लिये हमारे माननीय सदस्य चौधरी राजेन्द्र सिंह भी इस बात का प्रयतन करेंगे और ऐसी फैक्टरियों को आइडेन्टीफाई करैंगे जिनका गंदा पानी नहर में जाता है। मैं पूरी दिलचस्पी के साथ महकमे को कहूंगा कि जो गन्दा पानी इस कैनाल में गिरता है, उसको रोकने के लिये जरूर तुरन्त कदम उठाये जाएं।

चौ. जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय अभी माननीय सदस्य ने जिन 3–4 गांवों के नाम लिये हैं, वे मेरे हल्के से ताल्लुक रखते हैं। यह मसला केवल 3–4 गांवों का ही नहीं है बल्कि 7–8 गांवों का है। यह नहर 12–13 गांवों से होकर निकलती है। जिन

गांवों से निकलती है उनको इसका पानी नहीं मिलता। मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वहां पर एक्सटेशंन आफ मिरका माईनर के नाम से मंत्री जी पत्थर रख कर आये थे, लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। (विघ्न) मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक्सटेंश्न आफ मिरका माईनर का काम शुरू करवाने का कश्ट करेंगे? यह ठीक है कि जिन गावों का जिक्र मैंने किया है, उनको गुड़गांव कैनाल में से कोई आउटलैट नहीं दिया गया है। इस बारे, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन गांवों में पानी देने के लिये मंत्री जी निकट भविश्य में कोई इंतजाम करेंगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ऐसा है कि जो पत्थर पहले हमारे राज में रखे थे, उन पत्थरों को, जब इनकी सरकार आई, ये उठा कर ले गए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जिस रजवाहे की एक्सटेंशन के बारे में ये पूछ रहे हैं, इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास नहीं है। यदि ये जानना चाहते हैं तो सैपरेट नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जायेगा या ये फिर मुझे बाहर मिल लें, मैं पता करके इनको बता दूंगा कि इसकी क्या पोजीशन है।

चौ. अजमत खान: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया – 'No, Sir. Question does not arise' स्पीकर सर, गंगा घर से बाहर बह रही है और उसमें नहाने की इजाजत नहीं है। नहर का पानी गांवों से छाईसा होकर जा हरा है और ये कह रहे हें कि पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता। गुड़गांव नहर से एक

रजबाहा निकाल कर इन गांवों को पानी दिया जा सकता है (विघ्न) आपने जवाब तो दे दिया लेकिन बात यह है कि 10 गांवों में पानी का बन्दोबस्त हो सकता है यदि आप गुड़गांव नहर से छाईसा के मुकाम से रहबाहा बनाकर उटावड़ माईनर जो 32 किलोमीटर है, में पानी डाल दें। मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अगर पानी टेल पर नहीं पहुंचेगा तो मुलाजिमों को सस्पैंड करेंगे। टेल पर पानी न तो अभी तक पहुंचा है और न ही पहुंचाया जा सकता है जब तक इस बारे में सरकार कोई स्पैशल स्कीम न बना दे। जब तक कोई स्कीम न बने तब तक टेल पर पानी पहुंचाना संभवन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में आपका एक सैपरेट क्वैश्चन हैं आपने जो पूछना है वह उस सवाल के समय पूछ लेना। जब वह टेक अप होगा आपका यह सवाल भी आज ही आ रहा है।

चौ. अजमत खान: अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक माईनर का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया है और अब कब तक सरकार यह प्रबन्ध कर देगी?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पानी नहीं देंगे। जो मूल सवाल है शायद अजमत भाई ने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। यह सवाल छतर सिंह जी का है। अध्यक्ष महोदय, ये गुड़गांव नहर से सीधा मोघा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा आउटलेट नहीं दिया जा सकता। जो

तरीका है उसी के हिसाब से आउटलेट दिये जाएंगे। अजमत साहब, सवाल न. 193 आपका ही है जो लगा हुआ है। बाकी का जवाब तफसील से मैं आपको उसमें दे दूंगा।

चौ. फूल चन्द मुलाना: स्पीकर साहब, हमारे क्षेत्र में नहरें तो नहीं है लेकिन मारकण्डा नाम की एक नदी बहती है। मारकण्डा को लोग ऋशि मारकण्डा के नाम से भी जानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। पिछली दफा भी सदन में यह बात आई थी कि काला–आम में हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्टस ने, कुछ फैक्टरियां वहां पर लगा रखी हैं और उन फैक्टरियों का प्वायजनस आउटलेट सारे का सारा मारकण्डा में जाता है। इसकी वजह से बहुत से पशु मर गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन मेन सवाल से तो यह पैदा नहीं होता। अगला प्रश्न।

Construction of overbridge on railway line

***171. Shri Mohan Lal Pippal**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has taken up the matter for the construction of an over-bridge on the Rewari-Delhi railway line in Rewari city with the Government of India; if so, details thereof?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): जी हां। हरियाणा सरकार ने रिवाड़ी दिल्ली रेलवे लाईन पर क्रौसिंग नम्बर 57–बी रिवाड़ी

शहर में ऊपरगामी पुल के निर्माण संबंधी मामला भारत सरकार के साथ उठाया हुआ है। इस संबंध में इस पुल को भारत सकरार के रेलवे मंत्रालय के वार्शिक प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिये समय समय परी 1986 से अब तक 7 बार पत्र–व्यवहार किया गया है।

श्री मोहन लाल पिपल: स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार को यह मामला भारत सरकार को भेजे हुए 6 वर्श हो गए हैं। यह बहुत ही जरूरी मामला है। रिवाड़ी के अन्दर पुल न होने की वजह से 24 घंटे में से साढ़े 8 घंटे फाटक बन्द रहता है और ट्रैफिक जाम रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे आश्वासन देंगे कि यह पुल कब तक बन जाएगा?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से अभी तक इस बारे में लिखित रूप में कुछ नहीं आया है लेकिन जबानी बात हुई थी। हमने 27 फरवरी को भारत सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। श्री सी.के. जाुर शरीफ से दो बार बात भी हुई है। इनके साथ–साथ एक–दो पुल और भी बनने हैं। अभी तक भारत सरकार ने इस बारे में लिखित मन्जूरी तो नहीं दी है लेकिन उन्होंने कहा है कि भजन लाल जी आपकी जितनी भी स्कीमें हमारे पास हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही आपको सैंक्शन भी दे देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मुंख्यमंत्री जी बताएंगे कि हरियणा में इस तरह के कितने पुल बनाने का

मामला विचाराधीन है और हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को किन–किन पुलों के बारे में लिखा हुआ है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही जरूरी पुल थे, उनमें से कुछ की मन्जूरी आ चुकी है, और काम भी शुरू हो गया है जैसे कि करनाल, पानीपत, सोनीपत बड़खल, बाटा चौक फरीदाबाद की मन्जूरी हो चुकी है। इसके साथ ही एक हिसार में राजगढ़ रोड पर बनने वाले पुल की भी मन्जूरी आ चुकी है। इनके अलावा जो पुल बहुत ही जरूरी हैं जैसे सिरसा, डबवाली और कैथल में भी पुलों का निर्माण होना है, इस बारे में हमने भारत सरकार को लिखा हुआ हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी जल्दी से जल्दी मन्जूरी आ जाएगी। इसके साथ ही हमने भारत सरकार को यह भी लिखा हुआ है कि जो स्टेट के हिस्से का पैसा है, वह भी हम देने का तैयशर हैं।

श्री धर्मपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाशण्या में बताया था कि इन्होंने भारत सरकार से महेन्द्रगढ़, भिवानी और हिसार रोड को नैशनल हाई वे बनाने की सिफारिश की है।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो ओवर ब्रिज के बारे में है। आप रेलवे ब्रिज के बारे में सवाल कीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, रोहतक भिवानी रोड पर रोहतक में रेलवे पुल बनाना बहुत जरूरी है। वहां पर बड़ी

भारी भीड़ होती है। तो क्या मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, स्टेट में बहुत जगहों पर ऐसे पुल बनाने की जरूरत हो सकती है। भारत सरकार ने पुल बनाने के लिए कुछ नार्मज बनाए हुए है कि फाटक कितनी देर बन्द रहता है और वहां पर कितनी ट्रैफिक जमा रहती है। इन सभी बातों को देखकर ही रेलवे लाईन पर पुल बनाने का फैसला किया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगी कि जितने भी क्रोसिंग्ज हैं, क्या उन सभी जगहों पर ऐसे पुल बनाने का मामला विचाराधीन है क्योंकि आज आबादी भी बहुत बढ़ गई है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सभी क्रौसिंग पर पुल बनाना तो मुश्किल है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन मामलों में भारत सरकार ने कुछ नार्मज बनाए हुए हैं। उन्हीं के अनुसार भारत सरकार पुल बनाने की मन्जूरी देती है।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हिसार में छोटी लाईन पर पुल बनाने की मन्जूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी को पता है कि जो जी.टी. रोड है, उस पर बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ट्रैफिक होता है। अगर एक मिनट भी

फाटक बन्द हो जाए तो दोनों तरफ एक–एक किलोमीटर तक लाईनें लग जाती है। क्या मुख्यमंत्री जी यह प्रोवीजन करेंगे कि इस पुल का निर्माण फौरी तौर पर शुरू हो जाए?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है वह बहुत ही सही बात है कि वहां पर बहुत भारी प्रोब्लम है। उसमें दिक्कत यह है कि एक तरफ तो अस्पताल है और दूसरी तरफ समाधि है। हमने डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे यह काम लगाया हुआ है कि इस सारे मामले को देखे। हमारी यह कोशिश रहेगी कि इस पुल का निम्रण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: पीर चन्द जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हो?

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का तो जवाब आ गया है। परन्तु मैं इनसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दें।

श्री मोहन लाल पिपल: अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी में पुल का निर्माण कार्य शुरू होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर छोटी 5 लाईनें हैं। इतनी लाईनें सारे हिन्दुस्तान में कहीं और नहीं है। वहां पर फाटक बन्द होने से बहुत भीड़ हो जाती है इसलिये वहां पर पुल का बनना बहुत जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री जी इस पुल

को अगले साल तक बनाने का आश्वासन देंगे तो रिवाडी के लोग इनके धन्यवादी होंगे।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि रिवाड़ी एक बहुत बड़ा जंक्शन है लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि हिन्दुस्तान में कहीं ओर पांच लाईनें नहीं आतीं। भटिंडा में ही पांच गाड़ियों से ज्यादा आती हैं। लेकिन यह मामला जरूरी है इसलिये इस मामले को हम टेकअप कर लेंगे और भारत सरकार से बातचीत करके हम कोशिश करेंगे कि इसकी अगले साल आधारशिला रखें।

श्री राम पाल सिंह कंवर: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया है कि कुछ और भी ऐसे रास्ते हैं जिनकी स्टडी करा कर नार्मज के मुताबिक रिकमैंड करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल–काछुवा रोड पर हमारा एक ही कालेज है, क्या उसको मिलाने के लिये करनाल काछुवा रोड की स्टडी कराकर नामज के मुताबिक पुल का बनाने के लिये रिकमैंडेशन करेंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनका जो सुझाव आया है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिवाड़ी मीटर गेज का सबसे बड़ा जंक्शन है और वहां से बहुत गाड़ियां गुजरती हैं साथ ही यह आश्वासन भी दिया है

कि सरकार ओवर ब्रिज बनाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालेगी। मैं आपके माध्यम से एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पर यह ओवर ब्रिज बनना था, वहां अब बहुत आबादी बढ़ गयी है तथा काफी मकानाल बन गये हैं। कया सरकार उसी जगह पर यह पुल बनाने के लिय कृत–संकल्प है या किसी और स्थान का चयन किया गया है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ओवर ब्रिज बनाने के लिये और जगह का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि जहां रोड है, जहां फाटक है, वहीं पर पुल बन सकता है इसलिये पुल तो वहीं पर बनेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहां मकान बने हुए हैं, उनको किसी तरह से बचाया जाए और कोई दूसरा रास्ता मिल जाए।

श्री राम रतन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अलीगढ़ रोड पलवल से गुजरती है, क्या मुख्यमंत्री जी भारत सरकार से उस पर पुल बनवाने के लिये अपील करेंगे कयोंकि वहां से बहुत यातायात गुजरता है जिसके कारण बाई पास तक रोड जाम हो जाती है और काफी दूर तक यह जाम खड़ा रहता है? इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि वह यहां पर भी पुल बनवाने की कोशिश करें।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस पुल के लिए आज ही कहा है, अगर यह नार्मज के मुताबिक कंडीशन्ज को पूरी करता होगा तो इस केस को भी हम भारत सरकार को रिकमैंड करके भेजेंगे।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अगर वहां किसी कारण पुल नहीं बन सकते तो क्या आप रेल की लाइन के नीचे से रास्ता निकलवाकर पुल बनवाने की कृपा करेंगे क्योंकि ऐसा करने से खर्च भी कम आयेगा और रेल विभाग भी ऐतराज नहीं करेगा? मेरी दूसरी बात यह है कि क्या आप कुरूक्षेत्र को जगाधरी तक मिलाने के लिये कोई रेलवे लाईन बनवाने की कृपा करेंगे?

Mr. Speaker: This question does not arise out of the main question.

Land Irrigated by Uttawar Minor

***193. Chaudhri Azmt Khan**: Will the MInister for Irrigation and Power be pleased to state the total acreage of land covering Villages Maluka, Uttawar, Rupraka, Gohpur, Paharpur, Dhiranki, Pachanka, Jirali etc. by the Uttawar since its construction yearwise separately ?

Irrigation & Power Minister (Shri Shamsher Singh Surjewala): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Total acreage of land irrigated by Uttawar disty. as per available records is as under :-

(Figures in acre)

Year	Ropraka	Gohpur	Pachanka	Uttawar	Paharpur
1	2	3	4	5	6
1982-83	40	30	8	Nil	Nil
1983-84	78	53	28	Nil	Nil
1984-85	34	26	9	Nil	Nil
1985-86	37	27	15	Nil	Nil
1986-87	4	13	8	Nil	Nil
1987-88	5	13	10	Nil	Nil
1988-89	24	110	65	Nil	Nil
1989-90	29	119	68	Nil	Nil
1990-91	24	131	74	Nil	Nil

Note: Maluka, Dhhiranki, Jirali are not in the command of this channel.

चौ. अजमत खां: स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि नौ साल में 1082 एकड़ रकबे में जो पानी सिंचाई हेतु दिया गया है, वह वास्तत में इतने रकबे में नहीं दिया गया क्योंकि अगर किसी जोहड़ों में भी पानी दिया गया और रास्ते में किसी खेत के कोने में पानी चला गया तो उसकी भी गिरदावरी ली गयी

है। अगर 1082 एकड़ रकबे को सही मान लिया जाये तो क्या वजह है कि आज तक वह पूरा रकबा सिंचित नहीं हो पाया? दूसरी बात यह है कि जो तीन गांव इन्होंने दिखाये हैं वह भी इसी कमांड एरिये में आते हैं। इनमें एक गांव भालूका है जो इसकी टेल पर है और दूसरा गांव जरारी भी बिल्कुल इससे मिलता हुआ है इसके अलावा, गांव धीरनकी है जहां यह आउटलेट बने हुए हैं। अगर यह कमांड एरिये में नहीं है तो यहां पर आउटलैट कैसे बनाये गये हैं? इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इनकी टेल पर पानी पहुंचाने के लिये क्या कदम उठा रही है तथा कैसे इस इलाके में सिंचाई हो सकती है? असली बात मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि यह टेल हैड से ऊंचा है, इसलिये इस इलाके में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता हे। मैं 1985 से यह बात बार–बार कह रहा हूं और तभी से मुझे यह आश्वासन मिल रहा है कि यह ठीक हो जायेगा। इसलिये में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस नहर को दोबारा से ठीक करेगी या ऐसी ही रहेगी यह इसे कोई दूसरा रजबाहा बनाकर उससे बुर्जी न. 68 से या टेल की ओर से जोड़ देंगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तहकीकात बिल्कुल ठीक है। असल में मैंने इससे पहले प्रोफैसर छतर सिंर चौहान के सवाल के जवाब में यह कहा ही है कि यह जो गुड़गावां कैनाल है, इससे उटावड़ डिस्ट्रिब्यूट्री निकलती है। इस गुड़गावां कैनाल की कैपेसिटी 2200 क्यूसिक्स है

लेकिन इसमें 280 क्यूसिक्स पानी ही चलता है। इसमें से 110 क्यूसिक्स पानी इस उटावड़ डिस्ट्रिब्यूटरी में चलता है। इस डिस्ट्रिब्यूट्री से जिन जिन गांवों के मोघे या आउटलैटस तक पानी पहुंचता है, वह मैंने बता भी दिये हैं। इसके अलावा उटावड़ और पहाड़पुर दो गांवों में मैंने निल बताया है क्योंकि वहां पर टेल्ज पर पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि यह दोनों ही गांव टेल पर हैं। इसके बारे में हम क्या तजवीज करना चाहते हैं यह भी मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं ताकि उटावड़ डिस्ट्रब्यूट्री से टेल्ज तक पानी पहुंच सके। यह उटावड़ डिस्ट्रब्यूट्री 25 साल पुनानी बनी हुई है। यह 1966 में असल में ट्रायल के लिये बनायी गयी थी। 1968 में पहली बार इसमें पानी चला था। एक तो इसके पम्पस लिफ्ट कैनाल पर लगे हुए हैं, वे 25 साल पुराने हैं। इसके पम्पस को बदलने का विचार है। दूसरेस इस डिस्ट्रब्यूट्री की लाइनिंग करने की भी स्कीम बना रहे हैं। तीसरी दिक्कत यह है कि लिफ्ट कैनाल 33 किलोमीटर लम्बी है जोकि चल नहीं सकती। इसके लिये भी हम इन्तजाम कर रहे हैं। जो कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं, हम उसी हिसाब से इन्वैस्टीगेट का रहे हैं कि आउटलैटस को सीधे ही गुड़गावां कैनाल से जोड़ दिया जाये। योजना बनाकर जब यह आउटलैटस जुड जायेंगे तो इन गांवों की टेल ठीक हो जायेगी ओर वहां पर पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा, एक डिफैक्ट और है वहां का लैवल ठीक नहीं है। इसके अलावा, इनके इस इलाके में पानी की चोरी भी होती है। ओवर–साईज के आउटलैटस लगे हुए हैं और कोई इंडीपैडैंट फीडर नहीं है। इसके

लिये हम इंडीपैंडैट फीडर बना रहे हैं। नये पम्पस भी लगा रहे हैं लाईनिंग भी ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा जिन दो गांवों की टेल तक पानी नहीं पहुंचता, उनको दूसरे तरीके से यानी सीधे ही जोडने लग रहे हैं। यह सब होने के पश्चात हमें उम्मीद है कि किसानों को काफी राहत मिलेगी।

चौ. अजमत खान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे पता है, इसके अफसरों ने इस दफा एक नयी स्कीम बनाकर इनको दे दी है जिस पर लगभग 150 लाख रूपया लागत आयेगी। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि वह स्कीम अभी आपके पास ही पड़ी हुई है या मुख्यमंत्री महोदय के पास भेज दी है या अभी तक आपके पास भी आयी है या नहीं आयी है? अगर आयी है तो कब तक आप उसको मंजूरी दे दोगे?

श्री शमशेर सिंह सुरजवाला: मैं इनको यह बता देना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी भी वहां पर गये थे। इनके सामने भी यही सवाल आया था। महकमें के अफसरान स्कीम तैयार कर रहे हैं। स्कीम जब गवर्नमैंट के पास बनकर आ जायेगी तो उस पर विचार किया जायेगा। मैं आनरेबल मैम्बर की दिलचस्पी को देखते हुए उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर मैम्बर साहेब चाहे तो मेरे कमरे में आ जायें, वहां पर इंजीनियर चीफ इंजीनियर वगैरह सब को बुलाकर मामले को डिसकस करके एक्स्पीडाईट करने की कोशिश की जा सकती है।

Schools run under matching grant scheme

***166. Shri Mani Ram Keharwala & Chaudhri Verender Singh**: Will the Minister for Education be pleases to state-

(a) the number of 10+2 system High and Middle Schools for Girls functioning in the State under the matching grant scheme at present;

(b) the number of buildings of such schools as referred to in part 'a' above are under construction/completed; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the classes of above said schools in those buildings of which the first phase of the construction of buildings has been completed; if so, the time by which the classes are likely to be started ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): सूचना एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा उसकी तुलना में लाभ अधिक नहीं होगा।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, इस सवाल में हमने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि मैंचिंग ग्रांट योजना के अधीन लड़कियों के स्कूलों की बिल्डिंगज जो अंडर कंस्ट्रक्शज हैं, क्या वह कम्पलीट हो चुकी हैं अगर हो चुकी हैं तो उन नयी बिल्डिंग में क्लासिज कब तक चलाने का सरकार इरादा रखती है? हमने तो बस इतना ही पूछा था। इसमें कौन सी इतनी लेबर की बात थी कि अगल–अलग इनको रिकार्ड रखना पड़ता है। गर्ल्ज की

ऐजुकेशन के बारे में मुख्यमंत्री महोदय बार–बार यह कहते रहते हैं कि होनी चाहिये। बी.ए. तक इन्होंने फ्री भी किया है। इस बारे में हमारा ही सुझाव था। (व्यवधान व शोर) यह तो रिकार्ड की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 50–60 स्कूल्ज सारे हरियाणा में ऐसे होंगे जिनकी बिल्डिंग अब तक कम्पलीट हो चुकी होंगी। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उनमें यह कब तक क्लासिज शुरू कर देंगे? यह तो पालिसी की बात है। (व्यवधान व शोर)

श्रीमती शान्ति देवी राठी: स्पीकर साहब, भाई वीरेन्द्र सिंह जी ने यहां पर मैचिंग ग्रान्ट की बात कही। इस बारे में, मैं उनको बता देती हूं कि मैंचिग ग्रांट हमारा पंचायत एंव विकास विभाग देता है। यह स्कीम 1979 में चालू हुई थी और इस स्कीम में 1979 में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि लड़कियों के स्कूलों की स्पैशल बिल्डिंगें बननी चाहिये, चाहे वे रिपेयर का मामला हो, या फिर नई बिल्डिगें बनाने का मामला हो उनमें कुछ भौतिक सुविधायें जैसा कि पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चार दीवारी की सुविधा, वगैरह उसमें शामिल होनी चाहिये चूंकि यह सारी सुविधाएं हमारा पंचायत एंव विकास खंड के हिसाब से देता है लेकिन खंड के आधार पर हम अब तक यह साधन नहीं जुडा पाए हैं। भाई वीरेन्द्र सिंह जी, अपने क्षेत्र के स्कूलों के बारे में नई बिल्डिगों के बारे में अगर कोई जानकारी मांगना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूं।

15.00 बजे

Mr. Speaker: Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Minor/Sub-minors in District Hisar, Jind, Rohtak and Panipat

***201. Prof. Sampat Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any sanction has been accorded by the Government for the construction of minors/sub-minors during the period from June,1987 to-date in District Hisar, Jind, Rohtak and Panipat; and

(b) if so, the details thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला): (क) जिला हिसार, जीन्द व रोहतक में माइनर/सब–माइनर बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) 25 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनका अनुमानित व्यय 644.67 लाख रूपये है। इन स्कीमों का जिलेवार विवरण निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	जिला	स्कीमों की संख्या

1	हिसार	12
2	जीन्द	5
3	रोहतक	8
4	पानीपत	शून्य

Government College at Ratia

***164. Sh. Pir Chand**: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Ratia in District Hisar; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी):

(क) नहीं जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Parents Teachers Association

***244. Sh. Kitab Singh**: Will the Minister for Education be pleased to state the number of schools wherein Parents Teachers Associations have been constituted/functioning in the State at present?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शांति देवी राठी): ऐसे स्कूलों की संख्या 8127 है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Adhoc employees working in HUDA

21. Prof. Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the categorywise number of employees working in HUDA on adhoc basis for the last more than two years; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of the employees as referred to in part (a) above?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पिछले दो वर्शों से अधिक समय से जो कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनकी श्रेणीवार सूचना निम्न प्रकार से है:–

क्रम	पद संज्ञा	तदर्थ कर्मचारियों की संख्या
1	उप जिला न्यायवादी	1
2	सहायक जिला न्यायवादी	1
3	कनिश्ठ अभियन्ता	31

4	सहायक प्रारूपकार	1
5	लेखा सहायक	2
6	कम्प्यूटर आप्रेटर	1
7	बागवानी निरीक्षक	7
8	आशुलिपिक	6
9	लिपिक	112
10	अनुरेखक	13
11	फैरो–खलासी	2
12	चालक	2
13	सेवादार	26

(ख) जी हां।

Sulikhera, Dhand and Sabarwas minors

22. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) whether sulikhera Minor, Dhand Sub-minor, Sabarwas Minor and Pabra link minor/canal (Bhattu Kalan Assembly Constituency in District Hisar) have been sanctioned by the Government in 1989-90 and 1990-91; and

(b) whether the construction work on the minors as referred to in part (a) above has been started; if so, the present stage thereof, togetherwith details of amount, if any, spent thereon?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क) हां जी। सुलिखेडा माईनर, सबरवास माईनर व पाबडा लिंक चैनल के बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा क्रमशः वर्श 1990–91, 1989–90 व 1990–91 में दी गई है। ढांड सब माईनर को बनाने की स्कीम की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(ख) सबरवास माईनर व पाबड़ा लिंक चैनल नामक स्कीमों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं चुका है। इनकी वर्तमान स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

वास्तविक उपलब्धि

क्र. स.	स्कीम का नाम	भूमि	मिट्टी का काम	लाइनिंग	अब तक किया गया खर्चा	टिप्पणी
1	सबरवास माईनर	100 प्रतिशत	90 प्रतिशतृ	26 प्रतिशत	27.72 लाख	

2	पाबडा लिंक चैनल	40 प्रतिशत	6 प्रतिशत		12.88 लाख	भूमि के मुआवजे का भुगतान करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी एंव भूमि अधिग्रहण अधिकारी हिसार के पास 24.56 लाख रूपये जमा करा दिये गये हैं।
3	सुलिखेडा माईनर					भूमि के मुआवजे का भुगतान करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण अधिकारी हिसार के पास 17.00 लाख रूपये जमा करा दिये गये हैं।

Vacant Posts of Doctors/Nurses/Pharmacists

23. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) the number of posts of Doctors, Nurses and Pharmacists lying vacant in the Hospitals inthe State at present; and

(b) the number of Hospitals functioning in rented buildings in the State?

स्वास्थ्य मंत्री (बहित करतार देवी):

(क) हरियाणा राज्य के हस्पतालों में इस समय डाक्टरों/नर्सों तथा औशधकारकों के जितने पद रिक्त पड़े हैं उनकी संख्या निम्नलिखित है:–

1	चिकित्सक, एच.सी.एम.एस. I	4
2	चिकित्सक, एच.सी.एम.एस. II	43
3	नर्सों (स्टाफ नर्स/नसिंग सिस्टर/मैट्रन)	123
4	औशधकारक	23

(ख) हरियाणा राज्य में किराये के भवनों में कार्यरत हस्पतालों की संख्या शून्य है।

Building for Police Station

24. Prof. Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the districtwise number of Police Stations in the State; and

(b) the number of Police Stations out of that referred to in part (a) above, functioning in rented buildings?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्टेटमैंट ''क'' एवम् ''ख'' विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:–

स्टेटमैंट

(क) हरियाणा में कुछ 145 स्थाई थाने हैं जिनका विवरण जिला सहित इस प्रकार से है:–

जिले का नाम	स्थाई थानों की संख्या
अम्बाला	10
यमुनानगर	8
कुरूक्षेत्र	6
कैथल	7
करनाल	7
पानीपत	4
सोनीपत	7
रोहतक	11
हिसार	17
भिवानी	11
सिरसा	10
जीन्द	10

गुड़गांव	11
फरीदाबाद	14
रिवाड़ी	6
नारनौल	8
जोड़	145

(ख) स्थाई थानों में से किराये के भवनों में कार्यरत थानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

जिले का नाम		थानों की संख्या जो किराये के भवनों में कार्यरत है।
अम्बाला	1	पुलिस स्टेशन, पंचकुला
	2	पुलिस स्टेशन, जगाधरी
		पुलिस स्टेशन सदर, यमुनानगर
कैथल	1	पुलिस स्टेशन, ढान्ड
कुरूक्षेत्र		शून्य
हिसार	4	पुलिस स्टेशन, जाखल

		पुलिस स्टेशन, अगरोहा
		पुलिस स्टेशन, उकलाना
		पुलिस स्टेशन, भट्टूकलां
सिरसा	4	पुलिस स्टेशन, शहर डबवाली
		पुलिस स्टेशन, कालांवाली
		पुलिस स्टेशन, नन्थू सराये चौपटा
		पुलिस स्टेशन, डींग
जींद	2	पुलिस स्टेशन, उचाना
		पुलिस स्टेशन, पिल्लु खेड़ा
भिवानी	1	पुलिस स्टेशन, उचाना
		पुलिस स्टेशन, पिल्लु खेड़ा
भिवानी	1	पुलिस स्टेशन, उचाना
गुड़गावां	2	पुलिस स्टेशन, बिलासपुर
		पुलिस स्टेशन, नगीना
फरीदाबाद	1	पुलिस स्टेशन, सैन्ट्रल फरीदाबाद

रिवाड़ी	2	पुलिस स्टेशन, धारूहेड़ा
		पुलिस स्टेशन, जाटूसाना
नारनौल		शून्य
रोहतक	1	पुलिस स्टेशन, सिविल लाईन, रोहतक
पानीपत	1	पुलिस स्टेशन, समालख
सोनीपत		शून्य
करनाल		शून्य
जोड		22

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि जीरो आवर से सम्बन्धित है।

Mr. Speaker: There is no zero hour today. Please take your seat.

वर्श 1992–93 का बजट पेश करना

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will present the Budget for the year 1992&93.

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने वर्श 1992–93 के बजट अनुमान पेश कर रहा हूं। (तालियां)

इस वर्श हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक कठिनाई के दौर से गुजरी है। जिस समय कांग्रेस सरकार ने केन्द्र में सत्ता सम्भाली हमारी अर्थव्यवस्था काफी चिन्ताजनक हालत में थी। भुगतान की विशम स्थिति, बढती हुई महंगाई, विदेशी मुद्रा में कमी, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरती हुई साख जैसे मुद्दे राश्ट्र के सामने थे। इन सब कारणों से आयात कम करना पड़ा जिससे औद्योगि विकास में कमी आई। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र में कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। एक ओर हालात का सामना करने के लिए फौरी कदम उठाए गए और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के ढांचे में बुनियादी सुधार करने की कोशिश की गई। अब वित्तीय घाटे में कमी की गर्ठ है तथा बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक लगाने में सफलता हासिल हुई हैं इन साहसपूर्ण एंव नये कदमों के जरिये राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री जी की जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है।

राश्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात एवं नीतियों का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता हैं इसमें बढ़ती हुई मंइगाई पर रोक लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस वर्श के दौरान मंहगाई की दर 16.7 प्रतिशत तक पहुंची जो अब कम होकर लगभग 12 प्रतिशत हुई है। उत्पादन की प्रक्रिया को एक झटका लगा जिससे राश्ट्र के कुल घरेलू उत्पाद में भी काफी कमी आई। इस घड़ी में जब कि देश के स्तर पर अर्थव्यवस्था को

सम्भालने की कोशिशें हो रही हैं, हमारा भी यह फर्ज है कि हम भविश्य में ऐसे नाजक हालात से बचने के लिए अभी तक आवश्यक कदम उठाएं। इसके लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों, राज्य के प्रशासन और हरियाणा की जनता से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं।

आथिक सर्वेक्षण

देश की अर्थव्यवस्था में इतने उतार–चढ़ाव आए। यह एक सुखद स्थिति है कि इन सबके बावजूद हरियाणा की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है। ''हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1991–92'' की कापी माननीय सदस्यों को बांटी जा चुकी है। इसमें पिछले वर्श के दौरान राज्य की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वर्श 1990–91 के दौरान आरक्षण विरोधी आन्दोलन के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में उबार देखने में आता है। तुरन्त अनुमानों के अनुसार वर्श 1990–91 में राज्य की आय में स्थिर मूल्यों में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह बढ़ोतरी 17.3 प्रतिशत की है। अर्थव्यवस्था में अलग–अलग क्षेत्रों से प्राप्त घरेलू उत्पाद की जांच की जाए तो हमें पता चलता है कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में 13.1 प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत एवं तृतीय क्षेत्र में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्श 1990–91 के दौरान राजय के कुल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 49.2 प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र का 20.1 प्रतिशत तथा तृतीय क्षेत्र का 30.7 प्रतिशत योगदान रहा है।

1980–81 में मूल्यों के आधार पर 1989–90 में जहां 2134 रूपए प्रति व्यक्ति आय थी वहां 1990–91 में बढ़कर यह 3327 रूपए हुई है। यह बढ़ोतरी 6.5 प्रतिशत की है। वर्तमान मूल्यों में आधार पर 1989–90 में 6026 रूपए से बढ़कर प्रति व्यक्ति आय वर्श 1990–91 में 6936 रूपए हुई है।

वर्श 1991 के दौरान कीमतों में वृद्धि होती रही। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) मार्च 1990 में 177 से बढ़कर दिसम्बर 1991 में 201 हो गया जो कि 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हैं यह ओर बढ़कर दिसम्बर 1991 में 225 हो गया जोकि 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हैं इसी प्रकार राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) मार्च 1990 मैं 166 से बढ़कर मार्च 1991 में 192 हो गया जोकि 15.7 प्रतिशत की वृद्धि है। यह दिसम्बर, 1991 में और बढ़कर 210 हो गया जोकि 9.4 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है।

वर्श 1991–92 के राज्य बजट अनुमानों के आर्थिक एवं क्रियात्मक विश्लेशण से पता चलता है कि 205 करोड़ रूपए के सीधे पूंजी निर्माण के अतिरिक्त, 341 करोड़ रूपए का अतिरिक्त पूंजी निर्माण राज्य सरकार के योगदान से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में होना सम्भावित है।

वित्तिय संस्थानों की भूमिका

मैं राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में बैकों तथा वित्तीय संस्थानों की भूमिका का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं। इन संस्थाओं द्वारा वर्श 1990–91 के दौरान राजय में 798 करोड़ 65 लाख रूपए के कर्जे दिए गए। 31 मार्च, 1991 को कुल बकाया पेशगी 2376 करोड़ रूपए थी जबकि राज्य में इसी दिन बैंकों में जमा कुल रार्शि 3686 करोड़ रूपये थी। इस तरह बैंकों में जमा हुए धन तथा उन द्वारा दिए गए कर्जे का अनुमात देखा जाए तो वह 60 प्रतिशत बनता है। राजय के ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी इलाकों में यह अनुमान 58 प्रतिशत है। वर्श 1990–91 के दौरासन जो 798 करोड़ 65 लाख रूपए के कर्जे दिए गए उनमें से 72 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को, 15.4 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र को एवं 12.6 प्रतिशत तृतीय क्षेत्र को दिए गए। इन आंकड़ो से जाहिर है कि राज्य सरकार की अपनी कोशिशों के साथ–साथ इन संस्थाओं द्वारा दी गई पेशगियों से भी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ी मदद मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा भविश्य में भी राज्य की अर्थव्यवस्ाा में बढ़ोतरी के लिए यह योगदान दिया जाता रहेगा।

केन्द्रीय सहायता

केन्द्रीय करों में राज्यों को जो हिस्सा मिलता है वह वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। इस समय राज्य को यह हिस्सा नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिल रहा है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें घाटे वाले एंव

पिछड़े राज्यों को अधिक लाभ देने के पक्ष में हैं। चूंकि हरियाणा अपेक्षाकृत विकसित राज्य माना जाता है इसलिए यह सिफारिशें कोई उतसाहवर्धक नहीं थी। इस बारे मेरे पूर्वाधिकारी वित्त मंत्री ने अपने पिछले साल के भाशण में तफसील दी थी।

जहां तक केन्द्र से योजना सहायता का सम्बन्धहै वह जाने–माने गाडगिल फार्मूलें के आधार पर मिलती है। इस फार्मूले में समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वर्श 1990–91 में भी संशोधित गाडगित फार्मूले में कुछ परिवर्तन किए गए तथा हरियाणा को इस वश्य मिलने वाली सहायता इसके अनुसार मिल रही है। इसके बाद इस फार्मूले पर दिसम्बर, 1991 में राश्ट्रीय विकास परिशद की 43वीं बैठक में फिर विचार हुआ और कुछ और परिवर्तन करने का फैसला लिया गया। इस फार्मूले में जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय तथा कर जुटाने जैसे निर्णायक घटक है। पहले अधिक ''कर जुटाने'' पर राज्य को अधिक सहायता मिलती थी परन्तु अब हुए फैसले के अनुसार इसकी जगह ''पूरे वित्तीय प्रबन्ध'' को आधार माना गया है। राज्य के वित्तीय प्रबन्ध का मूल्यांकन भी सरकार के वित्तीय अनुशासन संबंधी कारगुजारी, विदेशी सहायता से चलाए जाने वाली स्कीमों को समय अनुसार पूरा करने तथा राश्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति आदि पर निर्भर करेगा। इन माप–दण्डों में से किसी में भी यदि राज्य की कारगुजारी सन्तोशजनक न हुई तो सम्बन्धित माप–दण्ड के तहत मिलने वाली सहायता में कमी होगी। इसलिए जरूरी है कि यदि हम इस

माप–दण्ड के अधीन पूरी सहायता चाहते है तो हमें एक सख्त वित्तीय अनुशासन की पालना करनी होगी। वर्श 1992–93 के दौरान शुद्ध योजना सहायता 113.45 करोड़ रूपए होगी जोकि इस वर्श 102.50 करोड़ रूपए है।

संशोधित योजना 1991–92

चालू वर्श के दौरान राज्य सरकार को गैर–योजना क्षेत्र में काफी अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ा। जहां तक इन अतिरिक्त खर्चों की तफसील का सम्बन्ध है, वह मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इन अतिरिक्त खर्चों के बावजूद महत्वपूर्व क्षेत्रों को पूरी धन राशि उपलब्ध करवाई गई है। वर्तमान वित्तीय वर्श के लिए हमारी वार्शिक योजना 765 करोड़ रूपए की मंजूर हुई थी, जोकि भारत सरकार द्वारा दो स्कीमें समाप्त करने के कारण कम होकर 760 करोड़ रूपए की रह गई। पिछली सरकार द्वारा लागू की गई वृद्धावसाि पैन्शन योजना में हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया तथा आर्थिक माप–दण्ड को आधार बनाया गया। यह योजना पहली जुलाई, 1991 से चालू की गई। किसी भी विभाग के लिए मंजूरशुदा खर्च में कटौती नहीं की गई। वास्वत में सरकार ने 'परिवहन' एवं 'जन कार्यो' के क्षेत्रों के प्रावधान में बढ़ोतरी की है। साथ ही साथ, जो राशि तय की गई थी उसको विभागों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया। इन सब मुदों का ध्यान रखते हुए इस वर्श राज्य की संशोधित योजना अब 727.97 करोड़ रूपए की निर्धारित

की गई है। वर्तमान वर्श के लिए यह संशोधित प्रावधान वर्श 1990–91 के वास्तविक योजना खर्च से लगभग 18 प्रतिशत अधिक है।

वार्शिक योजना 1992–93

आठवीं पंचवर्शीय योजना वर्श 1992–93, पहली अप्रैल, 1992 से शुरू होगी। इसके लिए योजना एवं नीति, योजना आयोग द्वारा राश्ट्रीय विकास परिशद के अनुमोदन से तैयार की गई है। राश्ट्रीय लक्ष्य नियम किए गए हैं जिनमें जनसंख्या पर नियन्त्रण पाने, साक्षरता, रोजगार के अवसर बढ़ाने एंव गांवों को स्वच्छ पीने के पानी की सप्लाई जैसे मुद्दों पर विशेश जोर दिया गया है। इन राश्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो हमें काम करना ही है। साथ में हरियाणा राज्य के रजत जयन्ती वर्श में हमने एक विशेश 25–सूत्री कार्यक्रम बनाया हैं यह 25–सूत्री कार्यक्रम विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का एक वक्तव्य है। वर्श 1992–93 की वार्शिक योना में राश्ट्रीय लक्ष्यों के साथ–साथ हमारे अपने कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। राज्य की 1992–93 की वार्शिक योजना के लिए 830 करोड़ रूपए का खर्च निर्धारित किया गया है, जोकि वर्तमान वर्श के संशोधित प्रावधान से लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। गांवों के विकास को तरजीह देने के लिए राजय सरकार वचनबद्ध है और इसलिए योजना खर्च का लगभग 71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखा गया है। (तालिंया) सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सेवा योजनाओं को प्राथमिकता दी

जाती रहेगी। इसके लिए 305.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जोकि कुछ योजना खर्च का 36.77 प्रतिशत है। कृशि एवं सहायक सेवाओं, जिसमें सहकारिता भी शामिल है, के लिए योजनागत 8.76 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के लिए 2.55 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के लिए 13.90 प्रतिशत, बिजली के लिए 23.50 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार के लिए 6.70 प्रतिशत, उद्योगों के लिए 2.98 प्रतिशत, विकेन्द्रित योजना के लिए 1.81 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों के लिए 1.23 प्रतिशत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

कृशि

हरियाणा राज्य हरित क्रान्ति के पहले दौर से गुजर चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम कृशि का विविधीकरण करके तथा बागवानी को प्रोत्साहन देकर क्रान्ति के दूसरे दौर के लिये प्रयास शुरू कर दें ताकि कृशि क्षेत्र हमारे किसानों के लिये अधिक लाभदायक बन सके। हमारी योजना है कि दालों और तिलहन, विशेश तौर पर सूरजमुखी व सोयाबीन की उपज को बढ़ावा दिया जाये। बागवानी को बढ़ावा देने के लिये हम योजनाबद्ध तरीके से फलों की नर्सरियां बना रहे हैं और अन्य सुविधाएं विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे किसान बागवानी का अपनाएं। वान्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सभी सुविधाएं प्राप्त करवाना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये हमारी औद्योगिक नीति में कृशि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन

देने के लिये विशेश सहूलियतें दी गई हैं। उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कुन्डली में एक फलों एवं सब्जी की आधुनिक मण्डी स्थापित करने की योजना है जिसमें कोल्ड–स्टोरेज, प्रोसैसिन्ग तथा यातायात की सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

कृशि क्षेत्र में हमीर जो उपलब्धियां हुई हैं उसका श्रेय हमारे मेहनती किसानों को जाता है। लेकिन राज्य सरकार भी किसानों को जरूरी सुविधायें देने में पीछे नहीं रही है। अनेक फसल विकास योजनाओं के तहत किसानों को इस वर्श लगभग 21 करोड़ 53 लाख रूपये की प्रत्यक्ष रियायतें दी गई हैं। ये रियायतें खादों, बीजों, घासपातनाशियों (Weedides & Pesticides) भूमि–सुधार तथा फव्वारा सैटों के जरिये सिंचाई साधनों में बढ़ोतरी के लिये दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार कृशि क्षेत्र को बिजली तथा सिंचाई जल बहुत ही रियायती दरों पर मुहैया करा रही है।

पशु पालन

कृशि अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पशुपालन एवं डेरी के विकास में हमारे प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे। वर्श 1991–92 के अन्त तक हरियाणा में 575 पशु अस्पताल तथा 719 पशु डिस्पैंसरियों की सुविधायें उपलब्ध होंगी। वर्श 1992–93

में दो पोली क्लीनीक, 100 नई पशु डिस्पैंसरियां खोलने और 40 पशु डिस्पैसरियों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

मत्स्य पालन

अगले वर्श की योजना में मछली पालन के लिये 2 करोड़ा रूपये का प्रावधान है। यह कार्यक्रम बनाया गया है कि 700 लाख मछली बीज का स्टाक तैयार हो तथा 26000 टन मछली का उत्पादन हो। राज्य में अगले वर्श एक अतिरिक्त मलयुक्त मछली पालन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सहकारिता तथा ऋण

हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भालने के पश्चात सहकारी कर्जो पर पिछले सात वर्शो का ब्याज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया। मुझे इस गरिमामय सदन को यह बताने में अत्यन्त खुशी है कि हमने उत्पीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ 43 लाख रूपये का ब्याज माफ किया हैं (तालियां) इससे 320066 किसानों तथा अन्य लोगों को लाभ पहुंचा है। सहकारी कर्जो पर ब्याज माफी के हमारे फैसले से लाभ प्राप्तकर्ताओं तथा सहकारी क्षेत्र में हमारे बैंकों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ हैं इस वर्श छोटी अवधि के कर्जो की वसूली 71 प्रतिशत हुई है जबकि पिछले वर्श यह 42.53 प्रतिशत थी। 28 फरवरी, 1992 तक कुछ मिलकार 63.47 प्रतिशत वसूली हुई है। पिछले दस वर्शो में वसूली की यह एक रिकार्ड उपलब्धि है। (तालियां) इसकी वजह से

सहकारी वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक अवस्था में अत्यधिक सुधार हुआ है। सहकारी बैंकों ने वर्श 1990–91 में 108 करोड़ 85 लाख के कर्जे दिए थे जबकि इन वर्श 28 फरवरी, 1992 तक 263 करोड़ 51 लाख रूपये के कर्जे दिए जा चुके हैं। इस दिशा में हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर चुके हैं। राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को ब्याज माफ करने के उपलक्ष में धनराशि की पूरी अदायगी भी कर दी है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।

सहकारी क्षेत्र में तीन नयी चीनी मिलों ने कैथल, महम तथा भूना में इस वर्श गन्ने की पिराई आरम्भ कर दी है। गन्ने की सभी किस्मों की कीमतों में तीन रूपये प्रति क्विटंल की दर से बढ़ोतरी की गई है। इससे गन्ना उत्पादकों को 15 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा। हरियाणा में गन्ने की कीमतें पूरे देश में सबसे ऊंची कीमतों में है। (तालियां)

दुग्ध क्षेत्र में वर्श के दौरान सुधार के उपाय किये गये हैं जिनकी वजह से हरियाणा दुग्ध विकास फैडरेशन की स्थिति सुधार की ओर अग्रसर हैं। दूध का मूल्य 75 रूपये प्रति किलोग्राम फैट से बढ़ाकर 90 रूपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया गया था। पहली मार्च से इसको और बढ़ाकर 95 रूपये प्रति किलोग्राम फैट तथा 11 मार्च से 100 रूपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया गया है। दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा 29 फरवरी, 1992 तक 350 लाख लीटर दूध की खरीद की गई है। सिरसार में एक लाख लीअर

प्रतिदिन की क्षमता वाला एक दुग्ध संयंत्र लगाया जा रहा है जिसकी दिसम्बर, 1992 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

सिंचाई

हमारी सरकार का ध्यान किसानों को पूरी मात्रा में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की ओर रहा है तथा इसके लिये हम वचनबद्ध हैं। नहरों के अन्तिम छोर वाले खेतों में तक पानी पहुंचाने के लिये हमने नहरों व रजबाहों से रेत साफ करवाने का अभियान बड़े पैमाने पर छेड़ा। कृशि उपज के लिये पूरा पानी उपलब्ध कराना जरूरी है। इस स्त्रोत का हमें भरपूर उपयोग करना होगा। विश्व बैंक परियोजना, जो इस साल 31 मार्च को समाप्त हो रही है, वे तहत चालू साल में बड़ी मात्राा में नहरो, रजबाहों ओर खालों को पक्का किया गया है। हमारा इरादा है कि हम इस मुहिम को अगले साल भी जारी रखें। इसके लिये विदेशी संस्थागत सहायता से एक और परियोजना हासिल करने के लिये भारत सरकार से बात चल रही है। राज्य के रेतीले इलाकों में पानी का भरपूर उपयोग करने के इरादे से फव्वारा सैटों तथा ग्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाया जा रहा है। अधिक पानी जुटाने के मकसद से, सतलुज–यमुना नहर परियोजना को पूर्ण कराने का मामला भी हमने भारत सरकार से उठा रखा है तथा हमें पूरी उम्मीद है कि यह जल्दी ही पूर्ण हो जायेगी। इस नहर परियोजना के लिये अगले साल के लिये 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (विध्न)

बिजली

हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद बिजली की पैदावार तथा सप्लाई में उत्साहजनक बढ़ोतरी हुई है। जहां वर्श 1990–91 के दौरान बिजली की प्रतिदिन औसत सप्लाठ 232 लाख यूनिट थी, 1991–92 में बढ़कर यह 282 लाख यूनिट हुई है। पिछली खरीफ के दौरान 2 अगस्त, 1991 के दिन 351 लाख यूनिट की रिकार्ड बिजली सप्लाई की गई। हमने उपलब्ध साधनों को बेहतर इस्तेमाल किया और इसी वजह से यह सब सम्भव हो सका। बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। यहां तक कि फरीदाबाद के पुराने प्लांट में भी रिकार्ड बिजली पैदा की गई जो जनवरी, 1992 में महीने में कुछ मिलाकर 10 करोड़ यूनिट से भी बढ़ गई। बिजली की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा कृशि क्षेत्र को सप्लाई किया गया। जहां पिछले वर्श देहाती इलाकों में बिजली की औसतन सप्लाइ 129 लाख यूनिट प्रतिदिन थी इस साल बढ़कर 168 लाख यूनिट प्रतिदिन हुई है। मौनसून के देरी के आने के बावजूद बिजली की अच्छी सप्लाई की वजह से हमारी कृशि उपज में काफी बढ़ोतरी हुई।

टयूबवैल कनैक्शनों के लिए बहुत बड़ी तादाद में दरखास्तें आई हुई थी। इसी वजह से चालू साल के दौरान 10000 टयूबवैलों के मूल लक्ष्य को बढ़ाकर 20000 टयूबवैलों को कनैक्शन देने का फैसला किया गया। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी है

कि हम 20000 टयूबवैलों को कनैक्शन देने का लक्ष्य न केवल पूरा करेंगे बल्कि इस लक्ष्य को पार करने की भी उम्मीद है। (तालियां)

बिजली बोर्ड का सम्बन्ध केवल बिजली की पैदावार तथा उसकी सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। हमारा इरादा है कि बिजली बोर्ड के प्रशासन को आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के मामले में भी चुस्त किया जाए। रजत जयन्ती वर्श में इसके लिए एक ऐसी स्कीम बनाने की योजना है जिससे बिजली बोर्ड के सब–डिवीजन स्तर तक उनकी कारगुजारी की समीक्षा हो और इस आधार पर उनमें एक कम्पीटिशन की भावना पैदा की जाए। कारगुजारी का मापदण्ड तकनीकी तथा व्यापारिक काम के अलावा यह भी होगा कि आम जनता की शिकायतों को दूर करने में किस सब–डिवीजन से सबसे अच्छा काम किया। इस मामले में सब–डिवीजन की कारगुजारी की परख पंचायतों, म्यूनिसिपल कमेटियों तथा दूसरे जन–संस्थानों के माध्यम से प्राप्त रिपोटों के आधार पर की जाएगी।

जहां आम जनता की शिकायतों को दूर करने को पूरा महत्व दिया जाएगा वहीं बिजली की चोरी आदि रोकने की दिशा में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में इस वर्श एक ऐसी स्कीम चालू की गई जिसके तहत लोग स्वेच्छा से बिजली की अपनी सही खपत के बारे में सूचना दें। इस स्कीम के तहत लोगों में उत्साह पाया गया तथा 59 हजार किलोवाअ के बराबर बिजली

के अतिरिक्त लोड की सूचना लोगों ने स्वेच्छा से दी जिससे 3 करोड़ रूपए की आमदनी बढ़ी।

अगले वर्श की योजना में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। पानीपत ताप बिजली घर में 210 मेगावाट की छठी यूनिट में काम चल रहा है जिसके लिए 45 करोड़ 85 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। यमुनानगर तथा बिजली घर में हरियाणा का हिस्सा है। इसके लिए हमने लगभग 13 करोड़ रूपए खर्च से जमीन मुहैया करवाई है तथा नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने भी शुरू के काम में 4 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का खर्च किया है। हम इसकी अन्तिम मंजूरी का मामाल भारत सरकार से उठाए हुए हैं तथा यह उम्मीद है कि इस प्रोजैक्ट को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की मन्जूरी जल्दी ही मिल जाएगी। इसके लिए अगले वर्श की योजना में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बिजली सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए यह जरूरी है कि एक मजबूत विवरण सिस्टम बनाया जाए। बिजली के ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 101 करोड़ 25 लाख रूपए का प्रावधान अपने वर्श की योजना में है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेणों में, विशेश तौर पर टयूबवैलों को, कनैक्शन देने के लिए अगले वर्श की योजना में 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

उद्योग

औद्योगिक विकास का राज्य की अर्थ व्यवस्था के विविधीकरण में विशेश महत्व है। राज्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उद्योग के प्रसार पर निर्भर करते हैं। राज्य सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा निवेश आकर्शित करने के लिए रियायतें/अनुदान की दरें बढ़ाई गई हैं और कृशि आधारित खाद्य पदार्थों तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों के लिए विशेश प्रोत्साहन रखे गये हैं। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के विचार से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त अनुदान एवं रियायतों का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग विकास की गर्ज से, जो विशेश सुविधाएं 27 खण्ड़ों तक सीमित थी, अब राज्य के 68 खण्डों में उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। अप्रवासी भारतीयों (N.R.Is.) को आकर्शित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों का आरक्षण, बने बनाये मकान, रिहायशी प्लाट प्रदान करना तथा दूसरी जरूरी सेवाएं देने का नई औद्योगिक नीति में विशेश प्रावधान है। हमें उम्मीद है कि 1992–93 के दौरान लगभग 40 बड़ी तथा मध्यम दर्जे की इकाईयां लगेंगी जिससे लगभग 3 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रशासकीय कठिनाईयों को दूर करने के विचार से कार्य प्रणाली का सरलीकरण किया जा रहा है तथा सभी सुविधाएं 'एक खिड़की सेवा' से प्रदान की जायेगी। राज्य में

इलैक्ट्रानिक्स और दूसरे उद्योगों के विकास के लिए 19 औद्योगिक सम्पदाओं को बिजली की कटौती से छूट देने का विचार है। औद्योगिक विकास के लिए हमने अगले साल के योजना खर्च में चालू साल के संशोधित योजना खर्च से लगभीग 24 प्रतिशत अधिक का प्रावधान कया है। इससे जाहिर है कि सरकार उद्योग के बढ़ावे को कितना महत्व देती है।

तकनीकी शिक्षा

बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या हम सबके लिये चिन्ता का विशय है। इस समस्या का हल युवकों की तकनीकी सक्षमता को बढ़ाने में है ताकि उन्हें अपने खुद के धंधे चलाने और तकनीकी उद्योगों में रोजगार के काबिल बनाया जा सके। इस उदेश्य को पूरा करने के लिए तकनीकी शिक्षा पर विशेश बल देने की योजना है ताकि युवकों को तकनीकी ज्ञान हासिल करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हरियाणा के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में 81 करोड़ रूपये की एक विश्व बैंक परियोजना स्वीकृत की गई है। चालू वित्त वर्श में इसके लिए 13 करोड़ 50 लाख रूपये का योजनागत प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिये संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने तथा ट्रेनिंग को आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं अनुसार बनाने का हमारा इरादा है और इसीलिये वर्श 1992–93 में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु 36 करोड़ 65 लाख रूपये के योजनागत खर्च का प्रावधान किया गया है। (तालियां)

विज्ञान एवं तकनीक

विकास कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करने में वैज्ञानिक तकनीक का अपना एक विशेश महत्व है। विकास योजनाओं को कैसे लागू किया जाए – इसमें ताजा तरीन दूरस्थ संवेदनशील तकनीक का प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इस तकनीक के प्रयोग को और बढ़ाया देने का हमारा कार्यक्रम है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों को इस वर्श दो और विकास खण्डों में चालू किया गया है तथा दो नये अतिरिक्त ऊर्जा ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के प्रसार और लोगों में उन्हें अपनाने की आदत डालने की हमारी कोशिश अगले साल भी जारी रहेगी।

श्रम एवम् रोजगार

राज्य में औद्योगिक उन्नति के लिये औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण अनिवार्य है। सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध है कि मजदूर वर्ग को न्यूनतम वेतन दरें उपलब्ध हों। रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना सरकार के लिए एक अहम मुददा है। हमें अन्य व्यवसायों में रोजगार के अवसर पैदा करने के तरीके अपनाने होंगे क्योंकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपनी सीमायें हैं। इसलिये हमारा प्रयत्न होगा कि युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जायें ताकि उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी मिलने में परेशानी न आये तथा वह अपने धन्धें भी शुरू कर सकें।

पात्र बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना भी जारी रखी जायेगी। मैं बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से भी अनुरोध करूंगा तथा उनसे अपेक्षा रखूंगा कि वह स्वःरोजगार को बढ़ावा देने में अपना पूरा सहयोग दें।

परिवहन

एक अच्छी परिवहन व्यवस्थान चलाने के मामले में हरियाणा को अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। चालू वर्श में एक नई ''एक्सप्रैस'' बस सेवा शुरू की गई है। इस समय नये बस अड्डों तथा वर्कशाप बनोन के लिये 11 स्थानों पर कार्य हो रहा है। तेल हमारे लिये एक बहुत कीमती साधन है तथा इसकी खपत को कम करने के लिये हरियाणा इंजीनियरिंग निगम ने पूर्ण रूप से धातु की बनी बस बाडियां बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। और अधिक चैसिस खरीदने के लिये इस साल हमने परिवजन विभाग का योजना सत्र 4.25 करोड़ रूपये बढ़ाया है। अगले वर्श के लिये जहां एक ओर सभी नकारा बसों को बदलने का कार्यक्रम है वहीं यह लक्ष्य भी है कि 636 नई बसें और खरीदी जायें। इसके लिये वर्श 1992–93 में 35 करोड़ 50 लाख रूपये के योजना खर्च का प्रावधान किया गया है जो कि इस वर्श के संशोधित प्रावधान से 31 प्रतिशत अधिक है।

सड़कें तथा पुल

हमारा ध्येय है कि राज्य में यातायात की उपलब्ध सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाए। इसीलिए हमारी सरकार ने सड़कों के रख–रखाव की ओर पूरा ध्यान दिया है। इसके लिए संशोधित बजट अनुमानों में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्केटिंग बोर्ड से भी साधन उपलब्ध करवाये गये है। मैं इस प्रयास को आगे भी जारी रखूंगा। सड़कों के रख–रखाव के लिये अगले वर्श के बजट में जहां राज्य की ओर से 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं यह निर्णय भी लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक रोड के रख–रखाव के लिये अतिरिक्त राशि मार्किटिंग बोर्ड तथा ग्रामीण विकास फण्ड से भी मुहैय्या करवाई जाएगी। जाहिर है कि अगले साल के लिये पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिये 19 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि योजना के अधीन रखी गई है। इस धन–राशि को हाई–वेज तथा प्रमुख जिला सड़कों को चौड़ा करने तथा उन्हें बढ़िया बनाने में खर्च किया जाएगा। राजकीय मार्ग नम्बर–1 को चार–लेनी बनाने का काम जारी है। इसी तरह बल्लभगढ़ से हरियाणा–उत्तर प्रदेश सीमा तक राजकीय मार्ग नम्बर–2 को भी चार–लेनी बनाने का कार्य शुरू हो चुका है तथा इसकी अप्रैल, 1995 तक पूरा होने की सम्भावना है।

पर्यटन

राज्य में शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां पर्यटन काम्पलैक्स स्थापित न किए गये हों। राजकीय व राज्य मार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में इस समय 42 टूरिस्ट काम्पलैक्स स्थापित किये जा चुके हैं। इन काम्पलैक्सों की सुविधाओं में विस्तार तथा नारनौल, हिसार, फतेहाबाद और राई में बनाये जा रहे काम्पलैक्सों को पूरा करने के लिये 150 लाख रूपये की राशि का प्रावधान अगले वर्श की योजना में किया गया है।

जन–स्वास्थ्य

एक समय था जब सभी गांवों में स्वच्छ पेय जल की सुविधा उपलब्ध करवाना एक स्वप्न था। 31 जनवरी, 1992 तक हरियाणा के 6745 गांवों में से 6677 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बाकी बचे 68 गांवों में भी इस वित्तीय वर्श के अन्त तक या सुविधा उपलब्ध करवोने का कार्य पूरा हो जाएगा। हरियाणा राज्य की यह एक और अनुपम एवं अद्वितीय उपलब्धि है। अब हमारा उदेश्य है कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्ध मिकदार को और बढ़ाया जाये। एक ऐसा नया कार्यक्रय चलाने का प्रस्ताव है कि बड़े गांवों में प्रति व्यक्ति 110 लीटर प्रतिदिन पानी की मात्रा मुहैय्या करवाई जाये ताकि गांवों में भी घरों में पानी के कनैक्शन दिये जाने शुरू हो सकें।

बड़े गांवों में लोगों के घरों में शौचालय बनाने का एक कार्यक्रम इस वर्श शुरू किया गया है। इस कार्यक्रय को हम

अगले वर्श भी पूरे जोर–शोर के साथ जारी रखेंगे जिसके लिये योजनागत खर्च में 2 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदूशित पानी की निकासी, मल निकाल तथा सिवरेज ट्रीटमैंट के सम्बन्धित कार्यक्रमों पर भी अगले वर्श कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इन सभी उदेश्यों को पूरा करने के लिये अगले वर्श की योजना के अधीन 39 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया है जो कि मौजूदा साल के संशोधित प्रावधान से 17 प्रतिशत अधिक है।

वन

पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने तथा बंजर भूमि के विकास के लिये वन स्त्रोतों का विकास अत्यधिक जरूरी है। अरावली की पहाडियों में पेड़ लगाने के कार्यक्रम की ओर विशेश ध्यान देना प्रस्तावित है। वर्श 1992–93 में वनों के अधीन क्षेत्र प्रसार के लिये 29 करोड़ 54 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा

अभी हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार राश्ट्रीय साक्षरता दर 52.11 प्रतिशत है जबकि इसके मुकाबले हरियाणा की साक्षरता दर 55.33 प्रतिशत है। हमारे लिए यह एक गर्व का विशय है कि पिछले दशक में हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर में

विशेश सुधार हुआ है। वर्श 1991 में राश्ट्रीय महिला साक्षरता दर 39.42 प्रतिशत हैं। हरियाणा में वर्श 1981 में महिला साक्षरता दर 26.89 प्रतिशत थी जो कि अब 40.94 प्रतिशत हो गई है। हम शिक्षा से सम्बन्धित स्कीमों को बढ़ावा देने तथा शिक्षा सुविधाओं का प्रसार करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारा ध्येय है कि 6 से 11 वर्श की आयु के शत प्रतिशत लड़के तथा लड़कियां स्कूलों में भर्ती हों। सरकार ने कालेजों में स्नातक स्तर तक तथा पोलिटैक्निकों एवं व्यवसायिक संस्थानों में लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के दरादे से यह फैसला भी किया गया है कि छठी कक्षा में बारहवीं कक्षा तक गरीब तबके से सम्बन्धित लड़कियों को वर्दियां तथा लेखन सामग्री भी मुफ्त उललब्ध कराई जाएगी। वर्श 1992–93 में लड़कियों के 100 प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे, 25 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर माध्यमिक, 25 माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उच्च विद्यालय और 10 उच्च विद्यालयों को 10+2 स्तर का किया जाएगा।

राज्य में स्कूलों की इमारतें काफी बुरी हालत में है। इसलिये हमने इमारतों की मुरम्मत तथा अतिरिक्त कमरे बनवाने की एक योजना बनाई। इसे पूरा करने के लिए अलग अलग स्कीमों से साधन जुटाए जायेंगे। स्कूली इमारतों की मुरम्मत अच्छी तरह तथा जल्दी कराने के लिये यह काम स्थानीय स्तर की कमेटियों को सौंपा जायेगा। शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार लाने

के लिये उत्कृश्ट शिक्षकों को विशेश इनाम तथा मेधावी छात्रों को वजीफे देने का प्रस्ताव है। वर्श 1992–93 में शिक्षा के प्रसासर के लिये योजना खर्च 50 करोड़ रूपया रखा गया है जो चालू साल में मुकाबले में 36 प्रतिशत अधिक है।

स्वास्थ्य सेवाएं

हमारी योजना है कि सन् 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हों। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी के सामान्य विकास कार्यक्रय को जारी रखने के साथ साथ राश्ट्रीय प्रतिरक्षण (Immunisation) कार्यक्रम को चलाने तथा जनसंख्या वृद्धि रोकने के राश्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भी विशेश ध्यान दिया जायेगा। पोलियो उन्मूलन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उदेश्य है और उम्मीद है कि अगले वर्श के अन्त तक हरियणा राज्य में पोलियों का विकार समाप्ति की अवस्था में होगा। यद्यपि हम जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में निरन्तर प्रयास करते रहे हैं, फिर भी हमारे लिये यह एक चिन्ता का विशय है कि हरियाणा की पिछले दस वर्शो में जनसंख्या वृद्धि की दर राश्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही है। हमें इस पर कामू पाना है तथा अपने नागरिकों को जनसंख्या व ृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरतों के प्रति जागरूक करना है। हम पहले ही विश्व बैक की सहायता से एक परियोजना कार्यान्वित कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत देहाती इलाकों में सहायक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप–केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। डाक्टरों तथा पैरामैडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण के

उदेश्य से पंचकूला में एक राज्य स्तर का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव हैं। वर्श 1992–93 में केवल इसी परियोजना के लिये 12 करोड़ 54 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

समाज कल्याण

पिछले वर्श अपना कार्यभार सम्भालने के पश्चात हमारी सरकार ने आर्थिक आधार से जुड़ी एक नई बुढापा पैन्शन योजना चालू की। इस योजना में पात्रता के लिए लाभ–पत्रों की उम्र 65 वर्श से कम करके 60 वर्श की गई है तथा 100 रूपये माहवार की दर से पैन्शन दी जाती है। इस योजना के तहत लगभग 7 लाख 40 हजार लाभ पात्रों को यह सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार पैन्शन का भुगतान समय पर कर रही है। इस समय जब मैं यह अर्ज कर रहा हूं, लाभ पात्रों को फरवरी मास तक की पैन्शन बांटी जा रही है। इस वर्श विकलांगों एवं विधवाऔं की पैन्शन की दरों को भी 75 रूपये प्रति मास से बढ़ाकर 100 रूपये प्रति मास की दर से पैन्शन दी जा रही है। हम इन स्कीमों को अगले वर्श भी जारी रखेंगे तथा एक ऐसा सिस्टम बनाने की ओर विचार किया जा रहा है जिससे कि वृद्धों, विकलांगों एवं विधवाओं को अगले वर्श पैन्शन का भुगतान समय पर किया जा सके।

जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा उत्तरदायित्व महिलाओं एवं बच्चों के विकास के प्रति

है। हरियाणा में पिछले 25 वर्शों में महिलाओं की हैसियत में एक विशेश बदलाव आया है। फिर भी महिलाओं के पूरे विकास तथा उन्हें विकास एवं सामाजिक बदलावा में सहभागी बनाने के लिये हमें विभिन्न क्षेत्रों में नए उपासय करने होंगे।

हरियाणा ने अपने 25 साल पूरे किये हैं तथा 8 मार्च, 1992 को अन्तर्राश्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिये रजत जयन्ती वर्श के दौरान शिक्षा, उद्योग, ऋण सुविधायें, ट्रेनिंग रोजगार तथा खेलों आदि के क्षेत्रों में विशेश सुविधाएं देने की घोशणा की है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं महिलाओं में शिक्षा लोकप्रिय बनाने के लिये आई.टी.आई. राज्य के पौलीटैक्निकों तथा व्यवसायिक संस्थानों में मुफ्त शिक्षा सुविधाएं देने का फैसला लिया गया है। महिला वर्ग की शिक्षा तथा ट्रेनिंग के लिये विशेश रूप से शिक्षा संस्थान खोले जा रहे हैं। इसके अलावा गरीब तबकों की बच्चियों के लिये स्टेशनरी व वर्दी की मुफ्त सुविधा दी गई है तथा हरिजन लड़कियों के लिये अतिरिक्त मासिक हाजिरी भत्ता भी दिया जाता है।

महिलाओं और बच्चों में शिक्षा प्रसार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकओं को पूरा करने के लिये संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या निधि की मदद से हमें 90 लाख डालर (लगभग 26 करोड़ रूपये) का एक नया प्रोजैक्ट मिला हैं जिसे महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, जीन्द रोहतक तथा कुरूक्षेत्र जिलों में लागू किया

जायेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को भली–भान्ति कार्यान्वित करने के मकसद से राज्य सरकार ने एक नया निदेशालय भी स्थापित किया है।

जहां एक और महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिये सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर हरियाणा वित्तीय निगम, हथकरघा निगम, इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा खादी एंव ग्रामीण उद्योग बोर्ड द्वारा मिलकर एक ऐसी विशेश स्कीम बनाई गढ़ है जिसमें महिलाओं को अपने खुद के काम धंधे शुरू करने के लिये मदद की जा सके। इस स्कीम के तहत जहां सस्ती दरों पर ऋण मुहैय्या करवाये जायेंगे वहीं अपने धन्धों में लगी महिलाओं को उनकी बनाई हुई वस्तुओं के बेचने के लिये भी सहायता दी जायेगी। गुड़गांव, हिसार, रोहतक तथा करनाल जिलों में विशेश रूप से महिलाओं के लिये सहमारी बैंक खोले जायेंगे ताकि उन्हें बचत करने का बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं को आसानी से ऋण देने का काम पूरा किया जा सके।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् समाज कल्याण क्षेत्रों में आधे से अधिक योजना खर्च महिलाओं के हिस्से में जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण स्कीम के तहत महिलाओं के लिये विशेश संस्थान चलाये जा रहे हैं। पौश्टिक आहार की योजना के तहत तो सारा खर्चा महिलाओं एवं बच्चों के लिये ही होता है। इसी तरह वृद्धावस्था पैन्शन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्रेनिंग आदि कार्यक्रमों में लगभग 40 प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ता महिलाएं हैं।

हमारी सरकार ने यह फैसला भी किया है कि महिलाओं के लिये बसों में सीटें आरक्षित की जाएं तथा पढ़ने वाली लड़कियों के लिये कुरूक्षेत्र, हिसार, व रोहतक में विशेश बसे सर्विस चालू की जाये। यह भी इरादा है कि अगले वर्श पूरे हरियाणा में बाल विकास परियोजनायें लागू की जायेंगी। ऐसा करने वाला हरियाणा देश में पहला राज्य होगा। शिक्षा, शिल्प, खेलों तथा बाल विकास परियोजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के इरादे से विशेश तौर पर इनाम दिये जाने की भी योजना है।

सामुदायिक विकास

ग्रामीण क्षेत्रों के विशेश तौर से गरीबों तथा आम जनता के विकास के लिये सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई जा रही है। जवाहर रोजगार योजना एवम समेकित ग्रामीण विकास योजना के कार्यक्रमों को पूरी लग्न के साथ चालू रखा जायेगा। राज्य में विशेशताः महिलाओं के लिये शौचालय सुविधायें प्रदान करने हेतु 2 अक्तूबर, 1991 से सरकार ने एक विशेश कार्यक्रम चालू किया है जिसके तहत कम खर्चे वाले शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। चालू वर्श में 36 हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निम्रण किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अगले वर्श भी पूरे जोर–शोर से चालू रखने का लक्ष्य है। राज्य के विकास एवम् जन स्वास्थ्य दोनों विभाग इसे क्रियान्वित करेंगे। उन्नत किस्म के धुओं रहित चूल्हों का लगाने के कार्यक्रम पर भी जोर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त हरिजन तथा पिछड़ी श्रेणी के लिये अधूरी चौपालों के पूरा करने तथा नई चौपालें बनाने के कार्यक्रम को भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मेवात के बैकवर्ड क्षेत्र के विकास के लिये हमने पहले से बहुत ज्यादा प्रावधान किया है।

विशेश संघटक योजना

विशेश संघटक योजना के तहत अनुसूचित एवम् पिछड़ी जातियों की भलाई के लिये विभिन्न प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं जोकि इन वर्गों के प्रति राज्य सरकार की जागरूकता का सबूत है। इन कार्यक्रमों के लिये इस वित्तीय वर्श में कुल संशोधित योजनागत प्रावधान का 10.9 प्रतिशत हिस्सा रख गया है जबकि अगले वर्श के लिये इसे बढ़ाकर 12.4 प्रतिशत कर दिया गया है।

खाद्य एवम् आपूर्ति

खाद्यान्यों की खरीद, जन वितरण प्रणाली एवम् उपभोक्ता संरक्षण कानून को सही तरीके से लागू करने का काम खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से किया जाता है। हमारा लक्ष्य यह है कि जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाये। इसे एक ठोस आधार प्रदान करने के लिये चाय, नमक तथा दालों जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी इन दुकानों के माध्यम से करवाने का कार्यक्रम है। उपभोक्ताओं के लिए लेमिनेटिड राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सरंक्षण कानून के तहत उनके

अधिकारों एवम् संरक्षण बारे उन्हें पूरी जानकारी दी जाये। इसके लिये अच्छी तरह से जन मानस में प्रचार किया जायेगा। राज्य भर में उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने वाले फोरम स्थापित किए जा चुके हैं।

सार्वजनिक इकाईयां

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस समय राज्य में बिजली बोर्ड को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र में 44 ऐसी इकाईयां है जो माल बनाने, व्यापारिक, एवम् अन्य वित्तीय गतिविधियों में लगी हैं। इन इकाईयों में 31 मार्च, 1991 तक कुल 1190.41 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। इसमें से राज्य सरकार ने 141.9 करोड़ रूपये का पूंजी हिस्सा तथा 230 करोड़ रूपये बतौर कर्ज दिया है। इसके अतिरिक्त 210.85 करोड़ रूपये ग्रान्ट के तौर पर भी इन्हें मिले है। शुरू से लेकर 1988–89 तक इन इकाइयों का कुल घाटा 49.13 करोड़ रूपये का था जो वर्श 1990–91 तक कम होकर 8.41 करोड़ रूपये रह गया है। जाहिर है कि पिछले 2 वर्शो में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के काम में सुधार हुआ है। वर्श 1990–91 के दौरान जहां 13 इकाईयों के काम में सुधार हुआ है। वर्श 1990–91 के दौरान जहां 13 इकाईयों में 14.27 करोड़ रूपये का घाटा रहा वहीं 23 इकाईयों ने 13.3 करोड़ रूपये का मुनाफा कमाया है। बाकी बची 8 इकाईयां ऐसी है जो या तो अभी हाल ही में शुरू की गई हैं या फिर जिन का कार्य क्षेत्र लाभ या हानि से सम्बन्धित नहीं है। वर्श 1990–91

के दौरान सभी इकाईयों के कुल मिलाकर 17.03 करोड़ रूपये का मुनाफा हुआ है जो कुछ निवेश का 1.43 प्रतिशत है। ग्यारह ऐसी इकाईयां है जिनकी अब तक की कुल हानि उने कुल पूंजी निवेश से ज्यादा है।

राज्य सरकार इस बात की आवश्यकता को पूरी तरह समझती है कि सार्वजरिक क्षेत्र की इन इकाईयों की कार्य विधि में सुधार लाया जाये। यद्यपि कुछ निगमों व बोर्डो ने वर्श 1990–91 के दौरान मुनाफा कमाया है फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि उन उपलब्धि एवम् कार्य प्रणाली पर नजर रखी जाये तथा उसे और बेहतर बनाने के लिये कार्य किया जाये। इसके लिये सरकार ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसके तहत इन इकाईयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में समय–समय पर विवेचना की जाएगी ताकि उनकी कार्यक्षमता व उत्पादकता में सुधार लाया जा सके। हमें उम्मीद है कि अगले वर्श कुछ और इकाईयों के कार्यो में सुधार होगा और वह लाभ कमाने की ओर अग्रसर होंगी।

सरकारी कर्मचारियों की सुविधायें

विकास एवम् कल्याण के कार्यो को लागू करने में सरकारी कर्मचारी हमारे सहभागी हैं। पिछले वर्श वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाशण में जो वायदे किये गए थे वे सब हमने पूरे किये हैं। इसके इलावा इस वर्श में महंगाई भत्ते की दो अतिरिक्त

किस्तें कर्मचारियों को दी गई हैं जिससे राज्य सरकार लगभग 72 करोड़ रूपये का वित्तीय भार पड़ा है। वर्श 1990–91 के लिये 29 दिन के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस की अदायगी भी की गई है जिससे राज्य सरकार पर लगभग 23 करोड़ रूपये का वित्तीय भार पड़ा है। कर्मचारियों को अच्छे वेतनमान देने तथा उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सभी सम्भव उपाय किये हैं। वेतनमानों में भी अधिकतर विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने, वाहन खरीदने तथा अन्य उदेश्यों के लिये सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध करवाती है। इस उदेश्य हेतू धन के अभाव में कर्मचारियों को काफी समय तक इन्तजार करना पड़ता हैं इस वर्श में हमने काफी ऐसे केसों का निपटारा किया है। अगले वर्श के लिये भी कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अग्रिम सुविधा देने हेतु हमने 10 करोड़ 55 लाख रूपये का प्रावधान रखा है ताकि उन्हें कम से कम इन्तजार करना पड़े।

महिलाओं और बच्चों की अच्छी देख भाल सुनिश्चिन करने के लिये सरकार ने प्रसूति अवकाश की सीमा 3 मास से बढ़ाकर 6 मास कर दी है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि महिला कर्मचारियों को घरों के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक महिला कर्मचारी को एक वर्श में 20 दिन

का आकस्मिक अवकाश उपलब्ध होगा चाहे उसकी नौकरी कितने भी सम की क्यों न हो।

माननीय सदस्यगण मुझसे सहमत होंगे कि सीमित साधनों के बावजूद सरकार ने अपने कर्मचारियों को अच्छी–से–अच्छी सुविधायें दी हैं। इस समय सरकार के कुछ बजट का 35 से 40 प्रतिशत तक कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर खर्च होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कर्मचारी भी राज्य के विकास में अपना भरपूर योगदान करेंगे।

संशोधित अनुमान 1991–92

पिछले साल बजट भाशण के अनुसार चालू वित्त वर्श 95 करोड़ 20 लाख रूपये के घाटे से समाप्त होना था। वर्श के दौरान हमारी जरूरतें बढ़ी जिनके फलस्वरूप अब अन्दाजा यह है कि यह वर्श रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 135.96 करोड़ रूपये क घाटे से समाप्त होगा। राज्य सरकार के खाते में 31 मार्च, 1991 को 48 करोड़ 62 लाख रूपए के खजाना बिल थे। इनका हिसाब रखते हुए यह घाटा असल में 87 करोड़ 34 लाख रूपऐ का होना सम्भावित है।

वर्श के दौरान हमें बजट अनुमानों से अधिक खर्च करना पड़ा। लगभग 205 करोड़ रूपए का अतिरिक्त निवल खर्चा दो महंगाई भत्ते की किश्तों के मंजूर करने से हुआ। वर्श 1990–91 के लिए बोनस की राशि की अदायगी भी इसी वर्श की

गई। यद्यपि इसे कर्मचारियों के भविश्य निधि खाते में जमा करवाया गया तथापि इससे राज्य कोश पर लगभग 23 करोड़ यपये का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त सहकारी कर्जो पर ब्याज को माफ करने की उत्पादन प्रोत्साहन योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। इस स्कीम के तहत किसानों एवं अन्यौं को राहत देने के लिए हमें 50.43 करोड रूपए का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा। सड़कों और भवनों के अच्छे रख–रखाव के लिए 8 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई। सिंचाई विभाग की और बिजली खर्चे के काफी बकायाजात इकट्ठे हुए हैं जिनकी अदायगी तरीकेबद्ध रूप से करने का प्रस्ताव है। मौजूदा वर्श के संशोधित अनुमानों में इसके लिए 5 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धन राशि का प्रावधान किया गया। विकलांगों एवं विधवाओं की पैन्शन की दरें 75 रूपए मासिक से बढ़ाकर 100 रूपए प्रति मास की गई जिसकी वजह से हमें 3 करोड़ 30 लाख रूपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। वन विभाग द्वारा ली गई भूमि की दरों में बढ़ोतरी की वजह से 2 करोड़ 50 लाख रूपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ तथा जींद में चमड़े की फैक्टरी की अदायगियां देने के लिए एक करोड़ 67 लाा रूपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

इन सब अतिरिक्त खर्चों के बावजूद सरकार ने बेहतर रिकवरी करके तथा गैरउतपादक खर्चों में बचत करके एक संतुलन बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। राज्य में करों से प्राप्त आय

काो बढ़ाने के लिए उपाय किए गए जिससे हमारी करों से प्राप्त आय मे बजट अनुमानों के मुकाबले 46 करोड़ रूपए की कृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गैर–विकासात्मक खर्च को कम से कम करने के लिए विभिन्न कदम उइाए गए। जहां एक ओर यह प्रयत्न रहा कि गैर–उत्पादन खर्चों में कभी हो वहीं यह भी सुनिश्चिन किया गया कि विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पूरी धन राशि उपलब्ध कराई जाए। यह इन्हीं प्रयत्नों का फल ह कि हमारा राजस्व घाटाा कम होकर 30.25 करोड़ रूपए रह गया है जबकि बजट अनुमानों में यह 48.13 करोड़ रूपए तथा बजट भाशण के अनुसार 78.13 करोड़ रूपए का था।

बजट अनुमान 1992–93

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस सदन के सामने वर्श 1992–93 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। आगे दी गई तालिका में वर्श 1991–92 के संशोधित अनुमानों तथा वर्श 1992–93 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य की वित्तीय स्थिति दर्शाई गई है:–

रूपये करोड़ों में

संघटक			संशोधित अनुमान 1990–91	लेखे 1990–91	बजट अनुमान 1991–92	संशोधित अनुमान 1991–92	बजट अनुमान 1992–93
I.	**अवशेश –**						
	(क)	महालेखा कार की पुस्तकों के अनुसार	(–) 87.99	(–) 87.99	(–) 85.99	(–) 62.13	(–) 127.88
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–) 65.44*	(–) 65.44*	(–) 63.44*	(–) 70.21**	(–) 135.96**
	(ग)	प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98
II.	**राजस्व लेखा –**						

	प्राप्तियां	1946.10	1913.42	22.57.19	2281.55	2506.57
	खर्च	2043.28	1933.08	2305.32	2311.80	2557.87
	अधिशेश / घाटा	(–) 97. 18	(–) 19. 66	(–) 88. 13	(–) 30.25	(–) 51.30
III.	**पूंजीगत खर्च**	142.62	186.16	179.34	166.81	213.89
IV.	**लोक ऋण**					
	लिया गया ऋण	580.93	591.97	731.48	488.83	693.88
	भुगतान	302.01	296.33	414.14	230.27	363.16
	निवल	+ 278.92	+ 295.64	+ 317.34	+ 258.56	+ 330.72
V.	**कर्ज और पेशगियां**					
	पेशगियां	210.97	203.38	247.03	240.58	257.81

	वसूलियां	30.34	23.53	30.70	27.99	33.47
	निवल	(–) 180.63	(–) 179.85	(–) 216.33	(–) 212.59	(–) 224.34
VI.	आक्समिकता निधि					
VII.	**लोक लेखा**					
	प्राप्तियां	1204.90	2986.42	1216.83	1339.47	1382.12
	भुगतान	1061.39	2870.53	1092.13	1254.13	1255.78
	निवल	+ 143.51	+ 115.89	+ 124.70	+ 85.34	+ 126.34
VIII.	**वर्श के दौरान की स्थिति**					
	सकल प्राप्तियां	3762.27	5515.34.	4236.21	4137.84	4616.04

	सकल व्यय		3760.27	5489.48	4237.97	4203.59	4648.51
	अधिशेश/घाटा		+ 2.00	+ 25.86	(–) 1.76	(–) 65.75	(–) 32.47
IX.	वर्श के लेखो में इतिशेश						
	(क)	महालेखाकार की पुस्तकों के अनुसार	(–) 85.99	(–) 62.13	(–) 87.75	(–) 127.88	(–) 160.35
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–) 63.44	(–) 70.21	(–) 65.20	(–) 135.96***	(–) 168.43****
	(ग)	प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98
X.	निवल इतिशेश खजाना बिलों का समायोजन करने के बाद –						
	(क)	महालेखाकार की पुस्तकों के				(–) 79.26	(–) 111.73

		अनुसार					
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार				(–) 87.34	(–) 119.81
	(ग)	प्रतिभूतियों में निवेश				7.98	7.98

टिप्पणी –

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 1990 को निवेशित 76.75 करोड़ रूपये की बकाया राशि के खजाना बिलों की गणना इस लेखे में नहीं की गई है।

** भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 1990 को निवेशित 48.62 करोड़ रूपये की बकाया राशि के खजाना बिलों की गणना इस लेखे में नहीं की गई है।

*** वर्श 1991–92 में 48.62 करोड़ रूपये के खजाना बिल, जो संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं, का समायोजन करने के पश्चात् घाटा 87.34 करोड़ रूपये होगा।

**** वर्श 1991 को निवेशित 48.62 करोड़ रूपये के बकाया खजाना बिलों का समायोजन करने के पश्चात् वर्श 1992–93 का घाटा 119.81 करोड़ रूपये होगा।

तालिका में दिए गए विवरण से स्पश्ट है कि रिजर्व बैक के खातों के अनुसार वर्श 1992–93 का आरम्भ 135.96 करोड़ रूपए समाप्ति घाटा 168.43 करोड़ रूपए का होना सम्भावित है। रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 1991 के दिन राज्य सरकार के खातें में 48.62 करोड़ रूपऐ के खजाना बिलों का निवेश था। इस निवेश, जो कि मौजूदा वश्र में राज्य सरकार की आय बनी, को ध्यान में रखते हुए यह स्पश्ट हे कि वश्र 1992–93 का अनुमानित समाप्ति घाटरा 119.81 करोड़ रूपए होगा। जहां चालू साल के दौरान 65.75 करोड़ रूपए के घाटे का अनुमान है, 1992–93 के दोरान वश्र में घाटरा 32.47 करोउ़ रूपए होने की सम्भावना है। वर्श 1992–93 में केन्द्र चालित स्कीमों के लिए 156 करोड़ रूपए के अतिरिक्त 830 करोड़ रूपए के राज्य योजनागत खच्र का प्रावधान किया गया है। अगले वर्श के दौरान 51.30 करोड़ रूपए के राजस्व धाटे का अनुमान है। मुझे उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक उभार से यह राजस्व घाटा कुछ हद तक कम हो पाएगा। चालू वश्र के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 1992–93 के लिए राजस्व वसूली के अनुमान 225.02 करोड़ रूपए अधिक है। जहां तक राज्य स्रकार के केन्द्रीय करों में हिस्से का सम्बन्ध है वह उसी स्तर पर रखा गया है जो योजना आयोग द्वारा हमें बताया गया था। यद्यपि विभिन्न करों से प्राप्त होने वाली आय में बढ़ौतरी की विभिन्न दरें अपनाई गई हैं परन्तु सब मिलाकर इस वश्र के संशोधित अनुमानेां के मुकाबले अगले वर्श कर राजस्व में 14.2 प्रतिशत बढ़ौतरी का अनुमान हैं वर्श 1992–93 के दौरान

टैक्सों के अलावा प्रापत होने वाली अन्य आय में, इस वर्श के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 19.86 करोउ रूपए की कमी रहने का अंदेशा है। हमारा निवल लोक ऋण 330.72 करोड़ रूपए का होगा। करों एव. देसरे साधनों से प्रापत होने वाली आय के अनुमाान वास्तविकता अनुसार आंके गए हैं। ऐसा करते समय जहां आवश्यक हुआ नौंवे वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। गैर योजनागत खर्चो के निर्धारण में नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा योजना आयोग के अनुदेशों को आम तौर पर ध्यान में रखा गया है। राजस्व लेखों से जाहिर है कि गैर योजनागत खच्र में केवल साधारण वृद्धि हुइ है और इसे कम से कम रखने का प्रयास किया गया है। चालू वर्श के संशोधित अनुमानों के मुकाबले अगले वर्श के बजट अनुमानों में हमारी ब्याज अदायगियां 21 प्रतिशत बढ़ी हैं। इसकी वजह यही है कि योजनागत खच्र के लिए अधिक कर्जे लिए गए हैं। जहां तक दूसरे गैर–योजनागत खर्च का सम्बनध है उसमें अगले वर्श के लिए केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन बजट अनुमानों में 54.50 करोड़ रूपए के उस खर्चे का भी प्रावधान है जो सातवीं योजना तक पूर्ण हुई योजना सकीमों को चालू रखने के लिए गैर योजना साईड में स्थानान्तरित करने की वजह से बढ़ा। किसानों के खालों के कर्जे माफ किए गए थे जिसकी नाबार्ड कोा आदायगी करने के लिए 16 करोड़ 60 लाख रूपए का प्रावधान भी किया गया है। बिजली बोर्ड की देनदारियां काफी बढ़ी हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सिंचाई विभाग द्वारा बिजली के बिलों की अदायगी नहीं

की गई है। अगले वर्श के बजट अनुमानों में हमने 20 करोड़ रूपए की सिंचाई विभाग की तथा 10 करोड़ रूपए की जन–स्वास्थ्य विभाग की पुरानी देनदारियों की अदायगी करने के लिए प्रावधान किया है। अब हमने गांव–गांव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की है। अतः उसके सही रख–रखाव के एिल 8 करोउ़ रूपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान अगले साल के अनुमानों में किया गया है। जनवरी, 1992 तथा जुलाई, 1992 से मंहगाइ भत्ते की दाो किश्तें अगले वर्श देय हाोगी। इसके लिए वर्श 1992–93 के बजट अनुमानों में 70 करोड रूपए का एकमुस्त प्रावधान किया गया है। (तालियां)

16.00 बजे

मैं पहले ही कह चुका है कि वश्र 1992–93 की समाप्ति 119.81 करोड़ रूपए के घाटे के साथ होनी सम्भावित हैं माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हरियाणा जैसे राज्य के लिए इतना घाटा लेकन चलना कोई समझदारी की बात नहीं है। मैं इस मौके पर माननीय सदसयों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि योजनागत खर्चे के एक बड़े भाग को पूरा करने के लिए साधन कर्जे लेकर जुटाने पड़ते हैं। महालेखाकार द्वारा दिये गये लेखों में 31 मार्च, 1991 को राज्य का कुल कर्ज का भार 3068.44 करोड़ रूपए था। 31 मार्च 1990 के मुकाबले यह कर्ज 18 प्रतिशत अधिक हैं इस वर्श के संशोधित अनुमानों में पता चलता है कि इस साल के अन्त तक राज्य सरकार पर लगभग 3465

करोड़ रूपए का कर्ज होगा तथा अगले वित्तीय वर्श के अन्त तक यह कर्ज लगभग 3932 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। इन आंकड़ों से स्पश्ट है कि राज्य सरकार पर वर्श 1991–92 तथा वर्श 19992–93 के दौरान क्रमशः 13 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत कर्ज का भार बढ़ेगा। राज्य के कर्ज भार में वे कर्जे आते हैं जो हमें केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों, बाजारी उधार तथा विदेशी एजेंसियों द्वारा सहायता प्रापत प्रोजैक्टों के अधीन मिलते है। इसके अतिरिक्त छोटी बचतों के अधीन मिलने वाले कर्जो तथा कर्मचारियों के प्रोविडैन्ट फण्ड में जमा होने वाली राशि का प्रयोग भी योजनागत खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। वास्तव में यह कर्जे पूंजीगत व्यय तथा राज्य की परि–सम्पति में वृद्धि के लिए लिए जाते है। इन कर्जा पर की जाने वाली ब्याज की अदायगियों से यह साफ जाहिर है कि यह बहत मंहगा कर्ज है। चालू वर्श के दौरान ब्याज अदायगियों पर 310.94 करोड़ रूपये तथा अगले वर्श 337.26 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। इन आंकड़ो से पता लगता है कि इन कर्जो को हमें पूरे ध्यान और समझदारी के साथ खर्च करना चाहिए ताकि राज्य में परिसम्पति निर्माण हो और हमें उउससे अधिक से अधिक उत्पादन मिले। यह चिन्ता का विशय हे कि पिछले कुछ सालों से इन साधनों, जाोकि परिसम्पति निर्माण के लिये हैं, का प्रयोग राज्य के राजस्व खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। यह बात मानने की है कि हमें इस स्थिति से उबरना है। कहीं ऐसा न हो कि कुछ वर्शो के पश्चात हम भी कर्जे के दुश्चक्र में

फंस जायें। हमारे बेहद प्रयासों के बावजूद गैर योजनागत खर्च में वृद्धि होती रही है। इस वर्श केन्द्रीय सरकार के बजट से यह पता लगता है कि बजट अनुमानों के मुकाबले संशोधित अनुमानों के अनुसार उनके खर्चों में कमी आई है जबकि हमारे यहां स्थिति इसके विपरीत है। केन्द्रीय बजट के इस उदाहरण से हमें सबक सीखना चाहिए और ऐसे पर्याप्त उपाय करने आवश्यक हैं जिससे हमारी आमदनी और खर्च में अन्तर को घटाया जा सके।

इस घाटे को कम करने का एक अच्छा तरीका तो यह है कि हम अपने गैर योजनागत खर्चे में कमी करें। सके लिए मुझे सभी सरकारी विभागों के सहयोग की जरूरत है। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हमारा अगले साल का गैर–योजनागत खर्च संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों से कम हो और यदि कम न हो सकें तो भी यह बजट अनुमानों से बएने न पाए। गैर–योजनागत खर्चों में कमी की भी एक सीमा है तथा केवल खर्चों में कमी करने से ही हम इस घाटे को पूरा नहीं कर पाएंगे। वर्श के दौरान बढ़ी हुई मंहगाई तथा राजय की अर्थव्यवस्था पर इससे उत्पन्न दबावों की ओर मैं इस सदन का पहले ही ध्यान दिला चुका हूं। राज्य सरकार के लिए मौजूदा दरों पर सभी सेवाएं मुहैया करवाना बहुत कठिन हैं। परिवहन क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में खासी वृद्धि हुई है। हम यह भी चाहते हैं कि उपलब्ध परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा उन्हें और भी बेहतर बनया जाए। इसलिए परिवहन भाड़े की दरों में बढ़ौतरी

करके अगले वर्श लगभग 45 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय जुटाने का मेरा प्रस्ताव है।

पिछले वर्श करों के ढांचे में सुधार करने की ओर कुछ कदम उठाए गए थे। कुछ वस्तुओं पर करों की दरों में कमी करने के बावजूद हमारे कुल कर राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है। हम महसूस करते हैं कि राज्य के वर्तमान कर ढांचे में और भी सुधार करने की गुंजाइश हैं एक और तो इस बात की आवश्यकता है कि जिन चीजों की खपत गरीब तबके में सबसे जयादा हो उन पर करों की दरें कम की जाएं तथा दूसरी ओर यह भी आवश्यक हैं कि करो की दरें ऐसी भी न हों जिससे व्यापारी वर्ग को करों की चोरी करने के रास्ते अपनाने पड़े। हम अपना यह फर्ज समझते है कि एक ऐसा कर ढांचा तैयार करें जिसमें गरीबों को करों की चुभन न हो और व्यापारी वर्ग में इन करों की ईमानदारी से अदायगी करने की भावना पैदा हो। मेरा यह विश्वास है कि अच्छी कर वसूली का आधार करों की ऊंची दरें नहीं बल्कि ईमानदार करदाता है।

इसीलिए हमने कुछ वस्तुओं पर करों की दरें कम करने का फैसला किया है। इस समय राज्य में टायरों व टयूबों पर बिक्र कर 8 प्रतिशत हैं अब हमने झोटा बुग्गी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी तथा खच्चर गाड़ी जेसी पशुओं से चलने वाली गाड़ियों के लिए टायरों व टयूबों पर बिक्री कर समापत करने का निर्णय लिया है। (तालियां) इसी प्रकार ट्रैक्टरों के लिए टायरों व टयूबों पर बिक्री

कर की दर 8 प्रतिशत से कम करके 4.5 प्रतिशत, थ्री–व्हीलरों पर बिक्री कर 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत, चाय पर बिक्री कर 8 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत और माचिस पर बिक्री कर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। (तालियां) पिछले वर्श 25 रूपये तक की कीमत की रबड़ से बनी हवाई चप्पलों को कर मुक्त किया गया था। (विध्न) अब हमने गरीबों कोा राहत देने के लिए 25 रूप्ये तक की कीमत की हर किस्म की चप्पलों व जूतों को कर मुक्त करने का फैसला किया है। (विघ्न) रंगों तथा रसायनों (Dyes & Chemical) पर इस समय बिक्री कर की दर 8 प्रतिशत है। हमने फैसला यिा है कि जब यह Textile की Processing में प्रयोग हेतू एक रजिस्टर्ड डीलर को बेचे जाएंगे तो इन पर कर की दर 4 प्रतिशत होगी। वनस्पति घी पर केन्द्रीय बिक्री कर को 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। (तालियां) इस समय चने की दाल को छोड़कर बाकी हर किस्म की दालों पर 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर है। हमने अब यह फैसला किया है कि 'C' फार्म देने पर यह दर 2 प्रतिशत होगी।

माननीय सदस्य मुझसे सहमत हौंगे कि करों की दरों में इन रियायतों से आम आदमी व व्यापारी वर्ग दोनों को राहत मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी वर्ग भी सरकार का पूरा साथ देगा तथा राज्यकी कुछ कर राजस्व वसूली में वृद्धि होगी।

मेरा अन्दाजा है कि करों की दरों में राहतों के बावजूद, इन उपायों से हमें लगभग 15 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय होगी।

इन सभी उपायों से राज्य सरकार को 60 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आाय होने का अनुमान है जिससे हमारा 1992–93 का समाप्ति घाटा 59.81 करोढ़ रूपए रह जाएगा। यद्यपि में इस घाटे को ऐसे ही रख रहा हूं, मुझे उम्मीद हे कि हम इसको कम कर पाएंगे। केन्द्रीय करों के हिससे में कुछ और वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त रिक्त गैर–उत्पादक खर्चो में और कमी करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे गैर–योजनागत खर्चो में बजट अनुमानों से वृद्धि न हो। इन उपायों से इस घाटे को और भी कम करने में मदद मिलेगी।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आगामी वर्श का कुछ घाटा मेरे द्वारा प्रस्तावित घाटे से अधिक नहीं होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आगामी वर्श की योजना में शामिल विकास के कामों को मुकम्मल पूरा किया जायेगा। इस उदेश्य की पूर्ति के लिये मैं आप सभी विधायकों का, सरकारी कर्मचारियों का, वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों का और सबसे ज्यादा हरियाणा की जनता का सहयोग मांगता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन कर्मचारियों का आधार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इन बजट अनुमानों को सावधानीपूर्वक तैयार करने में बड़ी मेहनत की हैं इसमें

महाालेखाकार, हरियाणा ने विशेश रूप से हमारी सहायता की है। वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बजट अनुमानों को ठीक समय पर तैयार, संकलित तथा प्रस्तुत करेन में काफी मेहनत की है। राश्ट्रीय सूचना केन्द्र, हरियाणा की भूमिका भी विशेश रूप से सराहनीय रही है। उनकी सहायता से आपके समक्ष प्रस्तुत गेरयोजना बजट एवम् राजस्व प्राप्ति बजट को सफलतापूर्वक कम्प्यूटर से तैयार किया गया है। इस कार्य के निपटान में संघ क्षेत्र (यू.टी.) की प्रैस तााि हरियाणा की प्रैस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अब मैं यह बजट अनुमान सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द। (तालियां)

Walk Out

During the course of presentation of Budget by the Finance Minister, Prof. Sampat Singh, followed by his party members i.e. Janata Party, present in the House, staged a walk out stating that no provision had been made in the Budgget for Agriculture and Irrigation Sector.

Mr. Speaker: Hon'ble members, now the House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow.

***16.11 hours**

(The Sabha then *adjourned till 9.00 a.m., on Tuesday, the 17th March, 1992.)